



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 2017/आश्विन 17, 1939

No. 390]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2017/ASVINA 17, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 25 सितम्बर, 2017

सं. टीएमपी/28/2016—जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्न आदेशानुसार, एनएच-4बी, एसएच-54 पर टोल गेटों को बन्द करने की वजह से जेएनपीटी से गुजरने वाले कंटेनरों तथा अन्य कार्गो पर टोल प्रभारों के निर्धारण के अनुमोदन की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/28/2016—जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(सितम्बर, 2017 के 15वें दिन पारित)

यह मामला एनएच-4बी, एसएच-54 पर टोल गेटों के बंद होने की वजह से पत्तन के माध्यम से गुजरने वाले कंटेनरों तथा अन्य कार्गो पर टोल की वसूली के लिए जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. जेएनपीटी ने अपने पत्र सं. जेएनपी/एफआईएन/टीएमपी/2016 दिनांक 27 अप्रैल 2016 और ईमेल दिनांक 28 अप्रैल 2016 द्वारा एनएच-4बी और एसएच-54 पर टोल गेटों के बंद होने की वजह से जेएनपीटी के सभी गेट परिसरों के अन्दर और बाहर से गुजरने वाले कंटेनरों तथा अन्य कार्गो पर 01 मई 2016 से टोल प्रभारों की वसूली के लिए प्रस्ताव दाखिल किया था।

2.2. जेएनपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

- (i). एनएच-4बी और एसएच-54 की सड़कों पर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीटी) अर्थात् मुम्बई जेएनपीटी पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (एमजेपीआरसीएल) के टोल गेटों के कारण भारी यातायात भीड़ के मद्देनजर, सरकार ने 1 मई 2016 से टोल गेटों को बन्द करने और

एसपीवी अर्थात् एमजेपीआरसीएल द्वारा अपने टोल स्लाजाओं पर वाहनों पर टोल वसूल करने की बजाय सभी गेट कॉम्प्लेक्सों के अन्दर और बाहर जाने वाले कंटेनरों (प्रति टीईयू) और अन्य सामान्य कार्गो पर प्रभार वसूल किए जाने का निर्णय किया था।

- (ii). इस संबंध में, एमजेपीआरसीएल से प्राप्त पत्र सं. एमजेपीआरसीएल/एनएचआई/पीआईयू/पनवेल/टोल/ 2016/297 दिनांक 23-04-2016 एवं 25 फरवरी 2016 को संयुक्त सचिव (राजमार्ग) के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्तों की प्रतिलिपि भेजी गई है।
- (iii). कंटेनर तथा अन्य सामान्य कार्गो पर उपयुक्त प्रभारों की वसूली द्वारा राजस्व की अपनी हानि के लिए जेनपीटी को एमजेपीआरसीएल को क्षतिपूर्ति करनी होती है।
- (iv). टोल प्रभारों की वसूली के लिए गणना निम्नवत् है:-

क्र.सं.	विवरण	यातायात टीईयू/ मी.ट. में
क.	कंटेनरधुक्त कार्गो	4750000 टीईयू
	घटाएः वर्ष 2015-16 के लिए आईसीडी यातायात: 15.84% और वर्ष 2016-17 के लिए : 16.63%	789925 टीईयू
	घटाएः पोतांतरण कार्गो 2%	95000 टीईयू
	कुल यातायात सड़क मार्ग द्वारा	3865075 टीईयू
ख.	शुष्क बल्क (सीमेट) एवं अन्य	700000 मी.ट.
ग.	द्रव्य कार्गो (सड़क मार्ग द्वारा परिवहन किए जा रहे हैं)	
i).	खाद्य तेल और गुड़	1700000 मी.ट.
ii).	रसायन	700000 मी.ट.
iii).	टैंकरों द्वारा एचएसडी	1800000 मी.ट.
	सड़क मार्ग द्वारा कुल द्रव्य यातायात	2580000 मी.ट.
घ.	ख + ग का जोड़	3280000 मी.ट.
ड.	कुल शुष्क बल्क, अन्य तथा द्रव्य टीईयू में होंगे 3280000 मी.ट./12 मी.ट.	273334 टीईयू
च.	कुल यातायात जिसपर टोल वसूल किया जाता है (क+ड)	4138409 टीईयू
छ.	एनएचआई द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए सुविचारित कुल टोल वसूली (रु. में)	
	विरले एवं करनजादे (एनएच-4वी) रु. 77.38 करोड़	
	डस्टन फाटा (एसएच-54) रु. 21.68 करोड़	
	कुल रु. 99.06 करोड़	99,06,00,000
ज.	प्रस्तावित टोल दर प्रति टीईयू (जी/एफ)	रु. 239.36/ टीईयू पूणिकित रु. 240/ टीईयू
झ.	सड़क मार्ग द्वारा प्रहसित परियोजना कार्गो और द्रव्य के लिए दर	रु. 20/ मी.ट.
ञ.	सीमेट /एल.पी.जी. की रियायत दर	रु. 5/ मी.ट.

- (v). तदनुसार, जेनपीटी द्वारा प्रस्तावित टोल सड़क द्वारा प्रहसित परियोजना कार्गो तथा द्रव्य के लिए रु. 240/ टीईयू, रु. 20/ मी.ट. है और सीमेट के लिए रु. 5 प्रति मी.ट. है क्योंकि यह एक कीमत संवेदनशील कार्गो है। तथापि, एलपीजी के लिए भी रु. 5 प्रति टन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि बॉटलिंग स्टाट में जाने वाले खाली सिलेंडरों तथा भरे हुए सिलेंडरों के साथ वापिस परिवहन के लिए ट्रक सड़क नेटवर्क पर पहुंचते तथा उपयोग करते हैं। तथापि, पाइपलाइनों, आईसीडी यातायात, कार्गो पोतांतरण, आदि के माध्यम से गुजरने वाले द्रव्य कार्गो पर प्रभारों की वसूली नहीं की जाएगी।
- (vi). बीओटी परिचालकों से वसूल किए गए ऐसे प्रभार राजस्व हिस्सेदारी की वसूली के लिए देय नहीं होंगे क्योंकि यह आय नहीं है परन्तु भीड़ और यातायात जाम को कम करने के लिए गेटों पर टोल को समाप्त किए जाने की वजह से जेनपीटी के माध्यम से एसपीवी को प्रतिपूर्ति मात्र है।
- (vii). ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित नवी मुम्बई इंटरनेशनल एअरपोर्ट की चारदीवारियों पर मौजूदा एनएच-4वी (ए1-ई सेक्शन कि.मी. 3.600 से कि.मी. 27,270, डी-जी सेक्शन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 4.462) एसएच-54 (कि.मी. 5300 से कि.मी. 14850) और आम्र मार्ग (0.000 से कि.मी. 6200) को चौड़ा कर 6/8 लेन करने के कारण संशोधित प्रभार इसके पूरा होने और प्रभावी तारीख पर पहुंचने पर पर अलग से सूचित किया जाएगा जिससे संशोधित प्रभार वसूल किए जायेंगे।
- (viii). पत्तन एसपीवी अर्थात् एमजेपीआरसीएल को आय के नुकसान से बचाने के लिए 1 मई 2016 से ऐसे प्रभारों की वसूली करने के लिए प्रवृत्त है। औपचारिक ट्रेड नोटिस अलग से जारी किया जाएगा।

3.1. जेनपीटी 1 मई 2016 से टोल प्रभारों की वसूली करना चाहता है। इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना ग्रासमिक है कि किसी नई सुविधा अथवा नई सेवा के उपयोग के लिए दर की अधिसूचना हेतु कोई प्रस्ताव, कार्यदिशानिर्देशों के खंड 5.7.2 में यथा विनिर्दिष्ट, नई कार्गो सुविधा अथवा नई सेवा की शुरुआत की संभावित तारीख से कम से कम 60 दिन पहले टीएसपी को अग्रेषित करना होता है। तथापि, वर्तमान मामले में, जेनपीटी द्वारा 01 मई 2016 से टोल प्रभारों की वसूली लागू करने की इच्छा

के साथ 27 अप्रैल 2016 को जेनपीटी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, कार्य दिशानिर्देशों के खंड 5.7.4 के अधीन यथा अपेक्षित संबद्ध उपयोक्ताओं के साथ जेनपीटी द्वारा परामर्श के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। जेनपीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव भी अधूरा पाया गया था।

3.2. किन्तु सामान्य परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए 1 मई 2016 से जेनपीटी द्वारा टोल प्रभारों की वसूली अनुमोदित करने हेतु समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए और चूंकि सरकार ने मौजूदा टोल प्लाजा पर टोल की वसूली रोकने का निदेश दिया था तथा 1 मई 2016 इसके गेट कॉम्प्लेक्सों में जेनपीटी द्वारा टोल/उपयोक्ता शुल्क वसूल करने की बजाय, तथा 1 मई 2016 से प्रस्तावित प्रभारों की वसूली हेतु जेनपीटी के आशय को भी स्वीकार करते हुए कि विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीटी) को आय में नुकसान से बचाने के लिए है, जेनपीटी को कंटेनर, परियोजना कार्गो, द्रव्य कार्गो (खाद्य तेल तथा गुड़, रसायन, टैंकरों द्वारा एचएसडी, सीमेंट की रियायती दर तथा एलपीजी) जो सड़क मार्ग द्वारा परिवहन किए जाते हैं और जेनपीटी के परिसरों के सभी गेट के अन्दर और बाहर जाते हैं उन पर 1 मई 2016 से प्रस्तावित प्रभारों पर टोल निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम उपाय के तौर पर वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया गया था:

- (i). प्रस्तावित दरों की वसूली इस प्राधिकरण द्वारा दरों को अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाने तक तदर्थ आधार पर रहेगी।
- (ii). परिचालित की जाने वाली तदर्थ दरें और अंतरिम अवधि में लागू किए जाने वाले कार्यनिष्ठादान मानकों पर संबद्ध उपयोक्ताओं तथा जेनपीटी में परिचालन कर रहे बीओटी टर्मिनलों के साथ विचार-विमर्श अवश्य किया जाना चाहिए।
- (iii). यदि इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अंतिम दरें प्रस्तावित दरों से कम रहती हैं, तो अंतिम दरों तथा तदर्थ दरों के बीच अन्तर जेनपीटी द्वारा संबद्ध उपयोक्ताओं को वापिसी की जाएगी।

3.3. इस स्थिति के बारे में हमारे पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2016 द्वारा जेनपीटी को सूचित कर दिया गया था।

3.4. इसके साथ ही साथ, जेनपीटी से हमारे उपर्युक्त पत्र द्वारा कुछ सूचना भेजने का भी अनुरोध किया गया था ताकि प्रस्ताव को पूरा किया जा सके। जेनपीटी को भी सूचित किया गया था कि, जेनपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले सम्पूर्ण प्रस्ताव पर प्रासंगिक शेयरधारकों के साथ चर्चा परामर्श किया जाएगा और एक संयुक्त सुनवाई भी आयोजित की जाएगी तथा उसके बाद परामर्श कार्यवाहियों के दौरान एकत्रित समग्र सूचना को ध्यान में रखते हुए इस प्राधिकरण द्वारा एक आदेश परित किया जाएगा। इस के प्रतिसाद में, जेनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 24 मई 2016 द्वारा सूचना भेजी थी। हमारे द्वारा मार्ग गई सूचना तथा उसपर जेनपीटी का प्रतिसाद नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा मार्ग गई सूचना	जेनपीटी का प्रतिसाद
(i).	प्रस्ताव के संबंध में प्रासंगिक शेयरहोल्डरों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त।	<p>कार्यालय ज्ञापन सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37011/145/2014-पीपीपी दिनांक 13-04-2016 द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संप्रेषित शेयरहोल्डरों की बैठक के कार्यवृत्त भेजे गए हैं।</p> <p>(महाराष्ट्र राज्य में जेनपीटी से पत्तन संपर्क की 6/8 लेन की राजमार्ग परियोजना के संबंध में एसपीटी तथा टोल लगाने से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए 25 फरवरी 2016 को बैठक आयोजित की गई थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सिडको और जेनपीटी ने बैठक में प्रतिनिधित्व किया था। संदर्भित प्रस्ताव के लिए प्रासंगिक कार्यवृत्तों के अनुच्छेद नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-</p> <p>(i). टोल लगाने/उपयोक्ता शुल्क के संबंध में, यह बताया गया था कि इस सड़क का मुख्य उपयोक्ता जेनपीटी बद्ध यातायात है और टोल गेटों पर यातायात भीड़ पर विचार करते हुए तथा टोल लगाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने पर, इसपर सहमति बनी थी कि जेनपीटी द्वारा सड़क का उपयोग करने वाले पत्तन यातायात से अपने गेट कॉम्प्लेक्सों पर टोल/उपयोक्ता शुल्क तब तक वसूल किया जाए जब तक टोल ऋण देयता का पुनर्मुग्यतान नहीं हो जाता। मौजूदा टोल प्लाजाओं को हटा लिया जाएगा।</p> <p>(ii). जेरस(एच) ने सूचित किया है कि, माननीय मंत्री (आरटी एंड एच) ने कुल ऋण देयता का पुनर्मुग्यतान किए जाने तक 1 मई 2016 से अपने गेट कॉम्प्लेक्सों पर जेनपीटी द्वारा टोल/उपयोक्ता शुल्क की वसूली की जाए और मौजूदा टोल प्लाजाओं पर टोल पर रोक लगाने का निदेश दिया था।</p> <p>जैसाकि कार्यवृत्त के पैरा 2(i) में दर्ज किया गया है, परियोजना (एनएच-4वी और एसएच-54 को 6/8 लेन का बनाना) के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए रु. 2439.66 करोड़ निधियों की आवश्यकता होगी। जेनपीटी द्वारा एमजेपीआरसीएल के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक ईसीबी वित्तपोषण के माध्यम से निधियों की व्यवस्था की जा रही है।)</p>
(ii).	कार्यनिष्ठादान मानकों के साथ मसौदा दरमान।	<p>बिन्दु सं. 6.7 पर अध्याय-6, विविध प्रभार के अधीन निम्नलिखित को जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है:</p> <p>"6.7: टोल प्रभार/उपयोक्ता शुल्क:</p> <p>पत्तन जेनपीटी, एनएसआईसीटी, जीटीआई, एनएसआईजीटी एवं बीपीसीएल में सभी गेट कॉम्प्लेक्सों के अन्दर जाने और बाहर आने वाले कंटेनर (टीईयू) और अन्य सामान्य कार्गो पर शिपिंग लाइनों/एंजेंटों/टैंक फार्म परियालकों (सड़क मार्ग द्वारा डिलीवरी)/परेषिती आदि से निम्नलिखित प्रभार वसूल किए जाएंगे।</p>

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>टोल प्रभारों की राशि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>केंद्र (प्रति टोईयू)</td><td>रु.240/टोईयू</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>परियोजना कार्गो</td><td>रु.20/मी.ट.</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>द्रव्य कार्गो</td><td>रु.20/ मी.ट.</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>सीमेंट</td><td>रु. 5/ मी.ट.</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>एलपीजी</td><td>रु.5/ मी.ट.</td></tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	टोल प्रभारों की राशि	1.	केंद्र (प्रति टोईयू)	रु.240/टोईयू	2.	परियोजना कार्गो	रु.20/मी.ट.	3.	द्रव्य कार्गो	रु.20/ मी.ट.	4.	सीमेंट	रु. 5/ मी.ट.	5.	एलपीजी	रु.5/ मी.ट.
क्र.सं.	विवरण	टोल प्रभारों की राशि																		
1.	केंद्र (प्रति टोईयू)	रु.240/टोईयू																		
2.	परियोजना कार्गो	रु.20/मी.ट.																		
3.	द्रव्य कार्गो	रु.20/ मी.ट.																		
4.	सीमेंट	रु. 5/ मी.ट.																		
5.	एलपीजी	रु.5/ मी.ट.																		
		चूंकि यह टोल को समाप्त किए जाने के कारण लेवी है, इसलिए इससे जुड़े अलग से कोई पृथक कार्यनिष्ठादान मानक नहीं है।																		
(iii).	परामर्श किए जाने वाले उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों/बीओटी परिचालकों की सूची उनके संपर्क व्यारों जैस पत्राचार पता, फैक्स नं. और ई-मेल आईडी के साथ।	परामर्श किए जाने वाले उपयोक्ता संगठनों, बीओटी परिचालकों की सूची तथा जेएनपीटी द्वारा शेयरहोल्डरों को जारी ट्रेड नोटिस की प्रति भेजी गई है।																		
(iv).	संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में पत्तन के न्यासी बोर्ड के अनुमोदन की प्रति।	विषय प्रस्ताव 17 मई 2016 को हुई 8वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष विषय प्रस्ताव पेश किया गया था और न्यासी बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया था। (पत्तन ने एजेंडा सूची की प्रति भेजी है और कहा है कि बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त अलग से भेजे जाएंगे) (तत्पश्चात् जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 28 जून 2016 द्वारा बैठक के कार्यवृत्त अग्रेषित किए थे।)																		

4.1. प्रस्ताव की पावती देते समय, जेएनपीटी से हमारे पत्र दिनांक 3 जून 2016 द्वारा अनुरोध किया गया था कि ट्रेड नोटिस में तदर्थ दरों को अनुमोदित करने के समय इस प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को शामिल नहीं किए जाने का कारण बताएं।

4.2. अनुस्मारकों के बाद, जेएनपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 5 जुलाई 2016 द्वारा यह बताया गया था कि हालांकि ट्रेड नोटिस जारी करते समय, शर्तों को शामिल नहीं किया गया था, परन्तु जेएनपीटी ने केंद्र शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन (इंडिया) तथा अन्य स्टेक-होल्डरों के साथ एनएच-4वी तथा एसएच-54 पर टोल गेटों को बन्द करने से पत्तन से गुजरने वाले कंटेनरों तथा अन्य कार्गो पर टोल की वसूली करने के लिए विस्तृत बैठक की गई थी, जिसमें, यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि टीएमपी द्वारा अनुमोदित दर अंतिम रूप से लागू होगी जब यह टीएमपी से प्राप्त हो जाती है। इसपर भी चर्चा की गई थी कि, ट्रेड नोटिस द्वारा परिचालित दर एक तदर्थ दर है जिसे टीएमपी से आधिकारिक आदेश के प्राप्त होने पर अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, टर्मिनल परिचालक तथा टैक फार्म परिचालकों के साथ 29 अप्रैल 2016 को हुई दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की प्रति भेजी गई थी।

5. निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार, जेएनपीटी प्रस्ताव दिनांक 27 अप्रैल 2016, 28 अप्रैल 2016, हमारे पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2016 और जेएनपीटी पत्र दिनांक 24 मई 2016 की एक-एक प्रति संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किए गए थे। कुछ उपयोक्ता संगठनों तथा जेएनपीटी में बीओटी परिचालकों अर्थात् ऑल इंडिया लिविंग बल्क इमोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (ऐएआईलबीआईईर), गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल), फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईआई), न्हावा-शेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईजीटीपीएल) तथा न्हावा शेवा इंटरनेशनल केंद्र टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईसीटीपीएल) ने अपने पत्रों क्रमशः दिनांक 9 जून 2016, 10 जून 2016, 10 जून 2016, 14 जुलाई 2016 और 13 जुलाई 2016 द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजी थीं जिन्हें जेएनपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थीं। जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 जुलाई 2016 और 21 अक्टूबर 2016 द्वारा उपयोक्ताओं की टिप्पणियों पर प्रतिसाद दिया था।

6. उपयोक्ता संगठनों तथा बीओटी परिचालकों की टिप्पणियों पर प्रतिसाद देते समय, जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 जुलाई 2016 द्वारा निम्नलिखित निवेदन भी किए थे:-

- (i). पत्तन सङ्क संपर्क परियोजना के अधीन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पत्तन से मौजूदा सङ्क संपर्क में सुधार करने के लिए एनएचएआई, जेएनपीटी तथा सिडकों का शामिल करते हुए विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया था। प्रथम चरण में, एनएच-4वी, एसएच-54 तथा अमरा मार्ग को 4 लेन बनाने को हाथ में लिया गया था। एनएच-4वी को चौड़ा करने का कार्य 2005 में पूरा हो गया था और अमरा मार्ग को चौड़ा करने का कार्य वर्ष 2008 में पूरा हो गया था। एनएचएआई/एसपीटी ने इन सङ्कों पर टोल गेटों पर प्रभार वसूल करना शुरू कर दिया था और टोल एनएचएआई की नीति के अनुसार संग्रहीत किया जा रहा था।
- (ii). स्थानीय लोगों तथा भारी वाहन के मालिकों ने टोल वसूले जाने का विरोध किया था और परिवहन यूनियनों ने हड्डताल की घोषणा कर दी थी। इस मामले पर परिवहन यूनियनों, एनएचएआई तथा सिडकों के साथ चर्चाएँ की गई थीं और चर्चाओं के बाद रायगढ़ और नवी मुम्बई में पंजीकृत स्थानीय भारी वाहनों के लिए 50 प्रतिशत टोल वसूल करने का निर्णय लिया गया था। यात्री वाहनों को कुछ रियायतें दी गई थीं। इसके बावजूद, स्थानीय जनता ने टोल गेटों पर लम्बी लाइनों तथा सङ्कों पर भीड़ को लेकर समय-समय पर प्रदर्शन किया था।
- (iii). जेएनपीटी में वर्तमान में 4.2 मिलियन बीस समकक्ष इकाईयों (टीईयू) की क्षमता है और ~100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर परिचालन करता रहा है। जेएनपीटी में मौजूदा यातायात ज्यादातर सङ्कमार्ग (लगभग 80 प्रतिशत) तथा शेष रेल संपर्क के माध्यम से निकासित करता रहा है। तथापि, सङ्क क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन सङ्कों पर वर्तमान यातायात 60,000 पीसीयू की क्षमता के सापेक्ष 77,000 पीसीयू (पैसेंजर कार इकाईयों) का अनुमान लगाया गया है।

- (iv). वर्धित यातायात पर विचार करते हुए, एनएचआई ने एनएच-4बी, एसएच-54 को 6/8 लेन चौड़ा करने का कार्य हाथ में लिया था। भूतल परिवहन मंत्रालय के अनुसार, समग्र सड़क अवधारणा प्राथमिक तौर पर जेएनपीटी यातायात के लिए है और इसलिए, पत्तन परियोजना के वित्तपोषण के लिए रु. 2855 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से रु. 2600 करोड़ का ऋण प्राप्त करेगा। उक्त प्रयोजन के लिए, जेएनपीटी की उक्त एसपीवी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
- (v). जनता को हो रही असुविधा तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति के मददेनजर, जेएनपीटी में प्रहस्ति यातायात से टोल वसूल करने का निर्णय लिया गया था, टोल गेटों पर वसूली करने की बजाय, जिसकी वजह से यातायात जाम का कारण बन रहे थे।
- (vi). 6/8 लेन रोड के निर्माण की अवधि के दौरान संग्रहीत की जाने वाली टोल राशि को सड़क परियोजना के राजस्व पूर्वानुमान में लिया गया है। इसलिए, पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह को बनाए रखने के लिए इसे संग्रहीत किए जाने की जरूरत है।
- (vii). प्रस्ताव तैयार करने के पीछे सिद्धांत पत्तन यातायात के कारण राजमार्ग पर भीड़ को कम करना, सड़क पर निर्बाध आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए पत्तन गेटों पर टोल वसूल करने के लिए है। उपर्युक्त उपाय के परिणामस्वरूप, राजमार्ग पर यातायात भीड़ कम दिखाई दे रही है और परिणामस्वरूप पत्तन सड़कों पर कम भीड़ है। ट्रकों की लम्ही लाइन लगने से कानून और व्यवस्था की भी समस्या पैदा होती है और पत्तन गेटों आदि पर लगातार जाम लगते हैं।

7. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 15 जुलाई 2016 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, जेएनपीटी ने प्रस्ताव की पावर प्लाइंट प्रस्तुति दी थी। जेएनपीटी तथा संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों ने संयुक्त सुनवाई में अपने निवेदन रखे थे।

8.1. संयुक्त सुनवाई में हुई सहमति के अनुसार, जेएनपीटी से हमारे पत्र दिनांक 20 जुलाई 2016 द्वारा अनुरोध किया गया था कि कुछ सूचना/स्पष्टीकरण भेजे जाएं। अनुस्मारक दिनांक 8 सितम्बर 2016 और 24 अक्टूबर 2016 के बाद, जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2016 द्वारा प्रतिसाद दिया था। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना तथा उसपर जेएनपीटी का प्रतिसाद नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना	जेएनपीटी का प्रतिसाद
(i).	संयुक्त सुनवाई के दौरान, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने टोल प्रभारों की वसूली में उनके समक्ष पेश आ रही मुश्किल की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इस संबंध में, बीपीसीएल ने जेएनपीटी से संबद्ध से सीधे लेवी वसूल करने और टोल संग्रहण के लिए अपने टर्मिनल में जरुरी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्ति की थी। इस प्रकार, संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, जेएनपीटी इस मामले को देखे और बीपीसीएल के साथ प्रामार्श करने के बाद इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजे।	बीपीसीएल एलपीजी बॉटलिंग स्लांट के गेटों पर टोल वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि एनएचआई या जेएनपीटी में से किसी के लिए भी संग्रहण को विनियमित और मॉनीटर करना बहुत मुश्किल है और टोल की वसूली के कारण सड़क पर लगने वाली भीड़ से बचने का समग्र प्रयोजन बेकार हो जाएगा।
(ii).	संयुक्त सुनवाई के दौरान, टर्मिनल परिचालकों जैसे गेटवे टर्मिनल इंडिया प्रा० लिमिटेड (जीटीआईपीएल), न्हावा शेवा इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईजीटीपीएल) और न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्रा० लिं० (एनएसआईसीटीपीएल) ने प्रशासनिक तथा संबंधित लागतों के लिए वसूल राशि का 5 प्रतिशत रखने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया था और जेएनपीटी एक समाधान पर कार्य करने के लिए सहमत था। तदनुसार, जेएनपीटी मामले को देखे और अपना प्रस्ताव जमा करे।	प्रशासनिक तथा संबंधित लागतों के लिए वसूल राशि का 5 प्रतिशत रखने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में एनएसआईजीटीपीएल, एएसआईजीटीपीएल और जीटीआईपीएल द्वारा कही गई बात पर सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि चर्चा के समय अथवा एमओएयू में ऐसी व्यवस्था परिकल्पित नहीं की गई थी।
(iii).	इसके अलावा, जेएनपीटी ने तीन वर्षों की अवधि के लिए टोल प्रभारों की वसूली के लिए अनुमोदन की मांग की थी। युक्ति जेएनपीटी द्वारा प्रेषित अनुमान केवल वर्ष 2016–17 के लिए है, इसलिए जेएनपीटी तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमानों को लेखा में ले और तदनुसार प्रस्ताव तैयार करे तथा दाखिल करे।	2017–18 और 2018–19 के लिए अनुमानित टोल वसूली के संबंध में, योरे भेजने के लिए एसपीवी के साथ इसे लिया गया है।
(iv).	जेएनपीटी वर्ष 2016–17 के लिए निम्नलिखित के प्रत्येक का अनुमान लगाने के लिए आधार भेजे: (क). कुल कंटेनरयुक्त कार्गो 4750000 टीईयू की दर से (ख). 16.63 प्रतिशत की दर से सुविचारित आईसीटी यातायात की हिस्सेदारी। (ग). 95000 टीईयू की दर से पोतांतरण कार्गो की हिस्सेदारी। (घ). 700000 मी.ट. की दर से शुक्र बल्क (सीमेंट) और अन्य की हिस्सेदारी (ङ). द्रव्य कार्गो की हिस्सेदारी (सड़क मार्ग द्वारा परिवहन किया जा रहा है) (ि). खाद्य तेल और गुड 1700000 मी.ट. की दर से (ii). रसायन 700000 मी.ट. की दर से (iii). टैंकरों द्वारा एचएसडी 1800000 मी.ट. की दर से	वर्ष 2016–17 के लिए यातायात का अनुमान लगाने हेतु आधार मंत्रालय के संदर्भ सं. जेएनपी/सीएम(टी)यातायात लक्ष्य/2016–17 दिनांक 18 जनवरी 2016 पर हमारे पत्र पर आधारित है। उक्त पत्र के अनुसार, जेएनपीटी के लिए वर्ष 2016–17 हेतु घटक वार अनुमानित वार्षिक यातायात लक्ष्य, जैसाकि जेएनपीटी द्वारा एमओएस को संप्रेषित किया गया है, निम्नवत् देखा गया है:
क्र. सं.	घटक	लक्ष्य
1	द्रव्य (रसायन+पीओएल) (टन)	6,500,000
2.	शुक्र बल्क (सीमेंट) और अन्य (टन)	700,000

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>3</th><th>कंटेनर</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जेएनपीसीटी+एसडीबी (टन)</td><td>20,955,000</td><td></td></tr> <tr> <td>जेएनपीसीटी+एसडीबी (टीईयू)</td><td>1,650,000</td><td></td></tr> <tr> <td>एनएसआईसीटी (टन)</td><td>10,160,000</td><td></td></tr> <tr> <td>एनएसआईसीटी (टीईयू)</td><td>800,000</td><td></td></tr> <tr> <td>एनएसआईजीटी (टन)</td><td>5,080,000</td><td></td></tr> <tr> <td>एनएसआईजीटी (टीईयू)</td><td>400,000</td><td></td></tr> <tr> <td>जीटीआईसीएल (टन)</td><td>24,130,000</td><td></td></tr> <tr> <td>जीटीआईसीएल (टीईयू)</td><td>1,900,000</td><td></td></tr> <tr> <td>कुल कंटेनर (टन)</td><td>60,325,000</td><td></td></tr> <tr> <td>कुल कंटेनर (टीईयू)</td><td>4,750,000</td><td></td></tr> <tr> <td>सकल जोड़ (टन)</td><td>67,525,000</td><td></td></tr> </tbody> </table>	3	कंटेनर		जेएनपीसीटी+एसडीबी (टन)	20,955,000		जेएनपीसीटी+एसडीबी (टीईयू)	1,650,000		एनएसआईसीटी (टन)	10,160,000		एनएसआईसीटी (टीईयू)	800,000		एनएसआईजीटी (टन)	5,080,000		एनएसआईजीटी (टीईयू)	400,000		जीटीआईसीएल (टन)	24,130,000		जीटीआईसीएल (टीईयू)	1,900,000		कुल कंटेनर (टन)	60,325,000		कुल कंटेनर (टीईयू)	4,750,000		सकल जोड़ (टन)	67,525,000		
3	कंटेनर																																					
जेएनपीसीटी+एसडीबी (टन)	20,955,000																																					
जेएनपीसीटी+एसडीबी (टीईयू)	1,650,000																																					
एनएसआईसीटी (टन)	10,160,000																																					
एनएसआईसीटी (टीईयू)	800,000																																					
एनएसआईजीटी (टन)	5,080,000																																					
एनएसआईजीटी (टीईयू)	400,000																																					
जीटीआईसीएल (टन)	24,130,000																																					
जीटीआईसीएल (टीईयू)	1,900,000																																					
कुल कंटेनर (टन)	60,325,000																																					
कुल कंटेनर (टीईयू)	4,750,000																																					
सकल जोड़ (टन)	67,525,000																																					
इसे वर्ष 2016-17 के लिए जेएनपीटी के यातायात के रूप में माना जा सकता है।																																						
आईसीडी तथा पोतांतरण की हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 के लिए प्रहसित यातायात के वास्तविक मोड पर आधारित है। वर्ष 2016-17 के लिए द्रव्य यातायात वर्ष 2015-16 में प्रहसित द्रव्य कार्गो के आधार पर अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2016-17 में प्रहसित किए जाने वाले 65,00,000 मी.ट. के कुल अनुमानित द्रव्य कार्गो में से, द्रव्य कार्गो का कार्गो वार ब्योरा नीचे दिया गया है:																																						
(i). खाद्य तेल और गुड़ —	17,00,000 मी.ट.																																					
(ii). रसायन —	7,00,000 मी.ट.																																					
(iii).पीओएल एवं पीओएल उत्पाद —	41,00,000 मी.ट.																																					
कुल	- <u>65,00,000 मी.ट.</u>																																					
सभी खाद्य तेल और गुड़ तथा रसायन कार्गो टैंकरों का उपयोग करते हुए सड़क द्वारा आवागमन किये जाते हैं। पीओएल में से, 1,80,000 मी.ट. एचएसडी रिलायंस लि० से संबंधित है जो सड़क मार्ग द्वारा ले जाया जाता है और शेष द्रव्य कार्गो पाइपलाइन तथा रेल के माध्यम से ले जाये जाते हैं। इसलिए, वर्ष 2016-17 के लिए सड़क मार्ग द्वारा ले जाया गया कुल अनुमानित द्रव्य कार्गो 25,80,000 मी.ट. (17,00,000+7,00,000+1,80,000) है।																																						
(v)	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए चिरले एवं करनजाड़े (एनएच-4बी) के लिए ₹ 77.38 करोड़ और डस्टन फाटा (एसएच-54) के लिए ₹. 21.68 करोड़ की दर से अनुमानित कुल टोल संग्रहण है जोकि कुल मिलाकर ₹. 99.06 करोड़ होता है और जेएनपीटी द्वारा अपनी गणनाओं में आधार माना जाता है, इसे दस्तावेजी साक्ष्य/गणनाओं द्वारा प्रमाणित करें।	थोक कार्गो (सीमेंट) और अन्य कार्गो केवल सड़कमार्ग द्वारा ले जाया जाता है। एनएचएआई द्वारा चिरले एंड करनजाड़े (एनएच-4बी) के लए ₹ 77.38 करोड़ और डस्टन फाटा (एसएच-54) के लिए ₹ 21.60 करोड़ टोल संग्रह है।																																				
(vi).	पत्तन ने सीमेंट/एलपीजी के लिए ₹ 5 प्रति मी.ट. के रियायती टोल दर पर पहुंचने का आधार/गणनाएं नहीं भेजी हैं। रियायती टोल दरों पर पहुंचने के लिए आधार/गणनाएं भेजी जाएं।	सीमेंट तथा एलपीजी कीमत संवेदनशील घटक हैं और इसलिए 75 प्रतिशत रियायत पर विचार करते हुए ₹ 5/- की रियायती दर निर्धारित की गई है।																																				
(vii).	थोक कार्गो, द्रव्य कार्गो, सीमेंट तथा एलपीजी के मामले में टोल प्रभार प्रति टन आधार पर प्रस्तावित किए गए हैं। चूंकि टोल वाहनों के गुजरने के लिए वसूली दिखाई देता है, इसलिए प्रति टन आधार की बजाय प्रति वाहन आधार पर उपर्युक्त कार्गो मदों के मामले में टोल प्रभार निर्धारित करना उचित होगा।	थोक कार्गो, द्रव्य कार्गो, सीमेंट तथा एलपीजी के मामले में टोल प्रभार प्रति टन आधार पर अधिसूचित किए गए हैं क्योंकि यह (एनएच-4बी और एसएच-54 पर टोल गट के बंद होने के कारण) पत्तन सड़क के माध्यम से कार्गो गुजरने से संबंधित है। ट्रांसपोर्टरों से यह पहचान करना और वसूली करना मुश्किल हो जाएगा कि किस वाहन में घटक का परिवहन किया जाएगा। यह न केवल तार्किक है अपितु प्रशासनिक रूप से भी कार्यान्वित करना आसान है।																																				

8.2. 3 वर्षों की अवधि के लिए टोल प्रभारों की वसूली करने में उहैं समर्थ बनाने के लिए संयुक्त सुनवाई के दौरान जेएनपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, जेएनपीटी से निरूपित करने तथा 3 वर्षों की अवधि के लिए अनुमानों को लेखा में लेते हुए प्रस्ताव दाखिल करने का अनुरोध किया गया था। जेएनपीटी को समय-समय पर हमारे पत्रों दिनांक 8 सितम्बर 2016, 24 अक्टूबर 2016, 17 नवम्बर 2016, 06 दिसम्बर 2016, 14 फरवरी 2017 तथा 19 अप्रैल 2017 द्वारा स्मरण करवाया गया था।

9.1. इस परिप्रेक्ष्य में, जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 27 अप्रैल 2017 द्वारा प्रतिसाद दिया था। जेएनपीटी द्वारा किए गए निवेदन निम्नलिखित हैं:-

- (i). जेएनपीटी के अनुरोध के आधार पर, मुख्य जेएनपीटी रोड कम्पनी लिमिटेड (एमोपीआरसीएल) ने अपने पत्र दिनांक 3 अप्रैल 2017 द्वारा अगले तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित अनुमानित टोल संग्रहण भेजा था:

वर्ष	राशि
2016-17	रु. 103.93 करोड़
2017-18	रु. 109.12 करोड़
2018-19	रु. 114.58 करोड़

- (ii). इसके अलावा, 2017-18 तथा 2018-19 के लिए यातायात आंकड़ों के जेएनपीटी के पूर्वानुमानों के अनुसार नीचे दिए गए व्योरों के अनुसार हैं:-

क्र.सं.	घटक	वित्तीय वर्ष	
		2017-18	2018-19
1	द्रव्य (रसायन+पीओएल) टन	7,000,000	7,500,000
2	शुक्र थोक (सीमेंट) एवं अन्य (टन)	675,000	700,000
3	ब्रेक बल्क	60,000	70,000
4	कंटेनर		
	जेएनपीटी+एसडीबी (टन)	20,557,800	20,938,500
	जेएनपीटी+एसडीबी (टन)	1,620,000	1,650,000
	एनएसआईसीटी (टन)	10,152,000	10,152,000
	एनएसआईसीटी (टीईयू)	800,000	800,000
	जीटीआईपीएल (टन)	22,842,000	23,476,500
	जीटीआईपीएल (टीईयू)	1800,000	1,850,000
	एनएसआईजीटी (टन)	5,076,000	6,928,740
	एनएसआईजीटी (टीईयू)	400,000	546,000
	बीएमसीटीपीएल (टन)	1,903,500	6,345,000
	बीएमसीटीपीएल (टीईयू)	150,000	500,000
5	कुल कंटेनर (टन)	60,531,300	67,840,740
6	कुल कंटेनर (टीईयू)	4,770,000	5,346,000
	सकल जोड़ (टन)	68,266,300	76,110,740

- (iii). इसके अलावा ऐसे पूर्वानुमान के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए रु. 13.53 करोड़ की कमी को जोड़ने के बाद, 2017-18 तथा 2018-19 के लिए प्रस्तावित टोल दरें निम्नलिखित हैं:-

विवरण	2017-18	2018-19
प्रस्तावित टोल दर प्रति टीईयू	रु. 267/टीईयू	रु. 267/टीईयू
सड़क द्वारा प्रहसित परियोजना कार्गो तथा द्रव्य कार्गो के लिए टोर दर	रु. 22/ मी.ट.	रु. 22/ मी.ट.
सीमेंट/एलपीजी के लिए रियायती टोल दर	रु. 5/ मी.ट.	रु. 5/ मी.ट.

- (iv). प्रस्तावित दर पर पहुंचने के लिए विस्तृत गणना नीचे दी गई है:

- (क). वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए वार्षिक यातायात पूर्वानुमान और एमजेपीआरसीएल द्वारा यथा पूर्वानुमानित टोल आय वसूल करने हेतु वसूल किए जाने वाले प्रभारों की गणना दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	विवरण	यातायात टीईयू/मी.ट. में 2017-18	यातायात टीईयू/मी.ट. में 2018-19	कुल
क.	कंटेनरयुक्त कार्गो	4770000 टीईयू	5346000 टीईयू	10116000
	घटाना: आईसीडी यातायात वर्ष 2017-18 के लिए सुविचारित: 15 प्रतिशत वर्ष 2018-19 के लिए सुविचारित: 16 प्रतिशत	715500 टीईयू	855360 टीईयू	1570860
	घटाना: पोतांतरण कार्गो 2%	95400 टीईयू	106920 टीईयू	202320
	सड़कमार्ग द्वारा कुल कंटेनरयुक्त कार्गो यातायात	3959100 टीईयू	4383720 टीईयू	8342820
ख.	शुष्क बल्क (सीमेंट) एवं अन्य	735000 मी.ट.	770000 मी.ट.	1505000
ग.	द्रव्य कार्गो (सड़कमार्ग द्वारा परिवहन किए जा रहे हैं।)			
	सड़क द्वारा कुल द्रव्य कार्गो यातायात	2600000 मी.ट.	2600000 मी.ट.	5200000
घ.	ख + ग का जोड़	3335000 मी.ट.	3370000 मी.ट.	6705000
ड.	कुल शुष्क बल्क, परियोजना कार्गो और द्रव्य टीईयू में 3275000 मी.ट./12 मी.ट. होगा।	277917 टीईयू	280833 टीईयू	558750
च.	कुल यातायात जिसपर टोल संग्रहीत किया जाएगा (क+डं)	4237017 टीईयू	4664553 टीईयू	8901570
छ.	एमजेपीआरसीएल द्वारा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए सुविचारित कुल टोल संग्रह राशि	रु. 1091200000		
	जोड़ना: 2016-17 के लिए टोल वसूली में कमी।	रु. 135345323		
	2017-18 एवं 2018-1 के लिए अपेक्षित कुल टोल संग्रहण	रु. 1226545323	रु. 1145800000	2372345323
ज.	प्रस्तावित टोल दर प्रति टीईयू	रु. 267/ टीईयू	रु. 267/ टीईयू	
झ.	सड़कमार्ग द्वारा प्रहसित परियोजना कार्गो एवं द्रव्य कार्गो के लिए टोल दर	रु. 22 /मी.ट.	रु. 22 /मी.ट.	
ञ.	सीमेंट/एलपीजी के लिए रियायत	रु. 5 / मी.ट.	रु. 5 / मी.ट.	

(ख). वर्ष 2016-17 के लिए टोल संग्रहण में कमी दर्शाता विवरण।

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. में)
क.	एमजेपीआरसीएल के अनुमान के अनुसार टोल आय	1039300000
	घटाना: माह अप्रैल 2016 के लिए एमजेपीआरसीएल द्वारा संग्रहीत	83400000
	घटाना: मई 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान जेएनपीटी द्वारा वसूली	820554677
	टोल संग्रहण में कमी	135345323

9.2. पूर्व प्रस्ताव दिनांक 27 अप्रैल 2016 और संशोधित प्रस्ताव दिनांक 27 अप्रैल 2017 के बीच तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिकाबद्ध की गई है:

विवरण	पूर्व प्रस्ताव दिनांक 27-4-16 के अनुसार	संशोधित प्रस्ताव दिनांक 27-4-17 के अनुसार	
		2017-18	2018-19
प्रस्तावित टोल दर प्रति टीईयू	रु. 240/टीईयू	रु. 267/ टीईयू	रु. 267/ टीईयू
सड़कमार्ग द्वारा प्रहसित परियोजना कार्गो और द्रव्य कार्गो के लिए टोल दर	रु. 20/ मी.ट.	रु. 22/ मी.ट.	रु. 22/ मी.ट.
सीमेंट/एलपीजी के लिए रियायती टोल दर	रु. 5/ मी.ट.	रु. 5/ मी.ट.	रु. 5/ मी.ट.

10. दिया गया है कि जेएनपीटी ने वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए अनुमान भेजे हैं और चूंकि पहले प्रस्तावित टोल प्रभारों के सापेक्ष जेएनपीटी द्वारा अब प्रस्तावित टोल प्रभारों में बदलाव किए गए हैं, प्रासांगिक उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों तथा बीओटी परिचालकों के साथ परामर्श से जेएनपीटी के संशोधित प्रस्ताव को लेने का निर्णय किया गया था। तदनुसार, जेएनपीटी संशोधित प्रस्ताव दिनांक 27 अप्रैल 2017 की प्रति संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों/बीओटी परिचालकों को उनकी टिप्पणियों के लिए अत्रेष्ठित की गई थी। बीओटी परिचालकों जैसे गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल), न्हावा शेवा (इडिया) गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईजीटीपीएल) और न्हावा शेवा इटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईसीटीपीएल) ने अपने पत्रों क्रमशः दिनांक 15 जून 2017, 30 जून 2017 और 30 जून 2017 द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजी हैं जिन्हें जेएनपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में भेजा गया था। जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 28 जुलाई 2016 द्वारा बीओटी परिचालकों की टिप्पणियों पर प्रतिसाद दिया था।

11. संशोधित प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई 30 जून 2017 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, जेएनपीटी ने प्रस्ताव पर पावर प्लाइंट प्रस्तुति दी थी। जेएनपीटी तथा संबद्ध उपयोक्ताओं/संगठन निकायों ने संयुक्त सुनवाई में अपने निवेदन किए थे।
12. इसके अलावा, संयुक्त सुनवाई के दौरान, जेएनपीटी से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया था। तदनुसार, जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा प्रतिसाद दिया था। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण तथा उसपर जेएनपीटी का प्रतिसाद नीचे तालिकाबद्द किया गया है।

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	जेएनपीटी का प्रतिसाद						
(i).	जेएनपीटी 2017–18 एवं 2018–19 के लिए 15 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की दर से सुविचारित आईसीडी यातायात भेजे।	<p>वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए 15 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत की दर से आईसीडी यातायात के संबंध में, हम यह कहना चाहते हैं कि पिछले 3 वर्षों के लिए आईसीडी यातायात निम्नतवः है:</p> <table border="1"> <tr> <td>2014-15</td><td>18.65%</td></tr> <tr> <td>2015-16</td><td>17.27%</td></tr> <tr> <td>2016-17</td><td>14.66%</td></tr> </table> <p>तथापि, जून 2017 के दौरान इसमें सुधार हुआ है और हालांकि वित्तीय वर्ष 2017–18 अर्थात् अप्रैल से जून 2017 के लिए 13.4 प्रतिशत है और रेलमार्ग/सड़कमार्ग समानीकरण तथा अन्य प्रोत्साहन यह अनुमानित किया गया है कि आईसीडी यातायात 2017–18 के लिए 15 प्रतिशत और 2018–19 के लिए 16 प्रतिशत होगा।</p>	2014-15	18.65%	2015-16	17.27%	2016-17	14.66%
2014-15	18.65%							
2015-16	17.27%							
2016-17	14.66%							
(ii).	जेएनपीटी दोनों वर्षों के लिए 2 प्रतिशत की दर से पोतांतरण कार्गो के लिए आधार भेजें।	पोतांतरण कार्गो के संबंध में यह 2015–16 के लए 1.14 प्रतिशत और 2016–17 के दौरान 0.99 प्रतिशत था। यह उम्मीद है कि पोतांतरण कार्गो में वृद्धि होगी और इसलिए दोनों वर्षों के लिए 2 प्रतिशत पर विचार किया गया है।						
(iii).	जेएनपीटी सड़कमार्ग द्वारा आवागमन वाले द्रव्य कार्गो यातायात की मात्रा का आधार बतायें।	सड़कमार्ग द्वारा आवागमन वाले द्रव्य कार्गो यातायात की मात्रा के संबंध में, इसे सुरक्षा की दृष्टि से 26,00,000 की दर से स्थिर लिया गया है और जबकि 2016–17 में यह लगभग 34 लाख मी.ट. था। तथापि, यह आयात मात्रा, घटकों तथा रेल द्वारा आवागमन पर निर्भर करता है जो वर्ष दर वर्ष आधार पर भिन्न हो सकता है।						
2.	जेएनपीटी स्पष्ट करे कि सड़कमार्ग द्वारा प्रहस्तित परियोजना कार्गो तथा द्रव्य कार्गो के लिए रु. 22 प्रति मी.ट. की दर से टोल दर को परिणित किया गया है।	सड़कमार्ग द्वारा प्रहस्तित परियोजना कार्गो तथा द्रव्य कार्गो के लिए रु. 22 प्रति मी.ट. की दर से टोल दर के संबंध में, यह स्पष्ट करना है कि निर्धारित की गई दर विभिन्न प्रकार के कार्गो के लिए है और एक संयुक्त डिनोमिनेटर होना चाहिए, परियोजना कार्गो तथा द्रव्य कार्गो के लिए इसे 12 मी.ट. 1 टीईयू के समकक्ष लिया गया था। यह कट्टनर यातायात के पूर्व रूझान पर आधारित है और तदनुसार द्रव्य कार्गो तथा परियोजना कार्गो के लिए पूर्वानुमानित यातायात को टीईयू में परिवर्तित किया गया था और एक बार जब दर प्रति टीईयू 12 मी.ट. से विभाजित करते हुए रु. 267 निर्धारित की गई, दर रु. 22 प्रति मी.ट. परिणित होता है।						
3.	जेएनपीटी ने अपने प्रस्ताव में बताया है कि जेएनपीटी द्वारा कटेनरों तथा अन्य कार्गो पर टोल प्रभारों की वसूली विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात् मुम्बई जेएनपीटी पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (एमजेपीआरसीएल) को होने वाले राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए है। तथापि, संयुक्त संचिव (राजमार्ग), सड़क परिवाहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में 25 फरवरी 2016 को हुई शेयरधारकों की बैठक के कार्यवृत्त (जेएनपीटी द्वारा अपने पत्र सं. जेएनपी/एफआईएन/एफए/2016/2848 दिनांक 24 मई 2016 द्वारा यथा अग्रेषित) में जेएनपीटी ईसीबी के माध्यम से रु. 2439.66 करोड़ की निधिया जुटाने के बारे में उल्लेख किया गया था और एक बार कुल ऋण देनदारी के पुर्णभुगतान के बाद जेएनपीटी द्वारा टोल/उपयोक्ता शुल्क की वसूली बन्द कर दी जाएगी। प्रयोजन में स्पष्टता नहीं है जिसके लिए टोल वसूल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, जब ईसीबी से अपेक्षित निधियों को परिमाणित किया गया है, टोल गेटों के बन्द होने के कारण एसपीवी को होने वाले नुकसान को परिमाणित नहीं किया गया है।	यह सही है कि जेएनपीटी ने एसएच-54 और एनएच-4बी को 6/8 लेन का बनाये जाने के लिए वित्तपोषण हेतु 400 मिलियन डॉलर का ईसीबी ऋण उठाया है। वसूल किया जा रहा वर्तमान टोल फेस-1 के अधीन किए गए सुधार के कारण है और टोल सड़क के रुखराखाय के लिए वसूल की जा रही थी। सभी गेटों पर यातायात भीड़ से बचने के लिए, गेटों पर टोल वसूली को बन्द करने और जेएन पत्तन के माध्यम से गुजरने वाले कार्गो पर वसूली करने का निर्णय लिया गया था। टोल गेट के बन्द होने से एसपीवी को नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि यह जेएन पत्तन के माध्यम से गुजरने वाले कार्गो पर वसूल किया जा रहा है और एमजेपीआरसीएल को भेजा जा रहा है। समावित टोल सग्रहण पूर्वानुमान एमजेपीआरसीएल द्वारा प्रेषित किया गया है और यातायात पूर्वानुमान टोल दर के आधार पर परिणित किया गया है। जब बार 6/8 लेन का कार्य पूरा होने पर, संशोधित दरें ऐसे विस्तार पर प्रोद्भूत वृद्धि लागत और ऋण सेवा दायित्व तथा इससे जुड़ी अन्य लागतों को लिए परिणित की जाएंगी।						

13. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:-

- (i). एनएचआई द्वारा गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) ने सड़कों को 4 लेन बनाने का कार्य पूरा किया था जोकि वर्ष 2005/2008 में पत्तन संपर्क परियोजना के चरण-1 में जेएनपीटी से जुड़ा था और इन सड़कों पर टोल गेटों पर टोल गेटों की वसूली शुरू की थी तथा टोल चरण-1 के अधीन किए

गए सुधार और इन सड़कों के अनुरक्षण हेतु एनएचआई की नीति के अनुसार संग्रहीत किया जा रहा था। एसपीवी अर्थात् मुम्बई जेएनपीटी पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (एमजेपीआरसीएल) द्वारा बनाए गए टोल गेटों पर लम्बी लाइनों के कारण समय-समय पर एनएच-4बी तथा एसएच-54 पर भारी यातायात भीड़ के मददेनजर, सरकार ने, कारोबार को आसान बनाने की अपनी नीति के ध्यान में रखते हुए, उक्त टोल गेटों को 1 मई 2016 से हटाने का निर्णय लिया था चूंकि जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के लिए आबद्ध यातायात इन सड़कों का उपयोग करता है। इसलिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सड़क संपर्क का उपयोग करने वाले पत्तन सामान यातायात से टोल/उपयोक्ता शुल्क जेएनपीटी द्वारा अपने गेट कॉम्प्लेक्सों पर वसूल किया जाएगा। तदनुसार, जेएनपीटी टोल गेटों के बन्द करने के कारण होने वाले नुकसानों की एसपीवी को क्षतिपूर्ति करने के लिए कटेनरों, परियोजना कार्गो, द्रव्य कार्गो, सीमेंट तथा एलपीजी पर टोल प्रभारों की वसूली करने में समर्थ बनाने के लिए प्रस्ताव लेकर आया है।

- (ii). जेएनपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रारंभिक प्रस्ताव अप्रैल 2016 में था। यह प्रस्ताव केवल वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न कार्गो मदों पर टोल प्रभारों की वसूली करने में पत्तन को समर्थ बनाना था। तथापि, संदर्भित मामले पर हुई संयुक्त सुनवाई के दौरान, जेएनपीटी ने तीन वर्षों की अवधि के लिए टोल प्रभार अनुमोदित करने का अनुरोध किया था। इसलिए, जेएनपीटी से तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमानों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया था। लगातार अनुस्मारकों के बाद, जेएनपीटी ने अप्रैल 2017 में एनएचआई से अपेक्षित ब्योरे इकट्ठे करने के बाद अप्रैल 2017 में संशोधित प्रस्ताव भेजा था। मामले की कार्यवाही के दौरान जेएनपीटी द्वारा प्रेषित सूचना/स्पष्टीकरण के साथ जेएनपीटी के संशोधित प्रस्ताव को विश्लेषण में लिया गया है।
- (iii). जेएनपीटी ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में कहा था कि जेएनपीटी द्वारा कटेनरों तथा अन्य कार्गो पर टोल प्रभारों की वसूली टोल गेटों के बन्द करने के कारण उनके राजस्व की हानि के लिए एसपीवी अर्थात् एमजेपीआरसीएल की क्षतिपूर्ति करना है। तथापि, संयुक्त सचिव (राजमार्ग), सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में 25 फरवरी 2016 को हुई स्टेकहोल्डर्स के बैठक के बार्यवृत्त (जेएनपीटी द्वारा अपने पत्र सं. जेएनपी/एफआईएन/2016/2848 दिनांक 24 मई 2016 के कवर के अधीन यथा अप्रैलित) में उल्लेख किया गया है कि जेएनपीटी ईसीबी के माध्यम से 400 मिलियन डॉलर की निधियां उगाह रहा है और जेएनपीटी द्वारा टोल/उपयोक्ता शुल्कों की वसूली को बन्द कर देगा एक बार कुल ऋण देयता का पुनर्मुग्यतान हो जाए। इस संबंध में, जेएनपीटी ने स्पष्ट किया है कि वसूल किया जा रहा वर्तमान टोल सड़क में सुधार तथा रखरखाव के लिए वसूल किया जा रहा है और कि एक बार एसएच-54 तथा एनएच-4बी को 6/8 लेन बनाने का कार्य पूरा हो जाए, दरों पर दोबारा कार्य किया जाएगा ताकि विस्तार पर प्रोट्रॉफ लागतों, ऋण सेवा दायित्व तथा इससे संबंधित अन्य लागतों को लिया जा सके।
- (iv). जेएनपीटी द्वारा किए गए विशेष अनुरोध के आधार पर, जेएनपीटी को उसके अप्रैल 2016 प्रस्ताव में उसके द्वारा जेएनपीटी के सभी गेट कॉम्प्लेक्सों के अन्दर और बाहर जाने के लिए कटेनर, परियोजना कार्गो, द्रव्य कार्गो (याद्य तेल तथा गुड़, रसायन, टैकरों द्वारा एचएसडी, सीमेंट तथा एलपीजी की रियायती दर) पर यथा प्रस्तावित प्रभारों पर कुछ शर्तों के अधीन अंतरिम उपाय के रूप में टोल वसूल करने के लिए प्रायिकृत किया गया था, जैसाकि अदेश के पूर्व हिस्से में घहले ही बताया गया है।
- (v). चूंकि टोल प्रभार जेएनपीटी गेट कॉम्प्लेक्सों में वसूल किए जाने के लिए परिकल्पित टोल प्रभार, जेएनपीटी के अनुसार, जेएनपीटी में बीओटी परिचालक से अंगक्षा की जाती है कि वे टोल प्रभारों की वसूली करे और उसे जेएनपीटी को भुगतान किया जाएगा जो बाद में इसे एसपीवी को भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में, उक्त बीओटी परिचालकों का मत है कि चूंकि बीओटी परिचालकों को बिलिंग, संग्रहण तथा अन्य प्रशासनिक कार्य के लिए अतिरिक्त संसाधन तैनात करने होंगे, टर्मिनल को प्रशासनिक तथा संबंधित लागतों के लिए संग्रह राशि का 5-10 प्रतिशत रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। जेएनपीटी ने इस आधार पर संग्रह राशि की कुछ राशि रखने पर सहमति में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि चर्चा के समय अथवा एमओयू में ऐसी व्यवस्था परिकल्पित नहीं की गई थी। जेएनपीटी के अनुसार, टोल तो नियमित बिल में केवल एक लाइन मद मात्र है, जेएनपीटी टोल के संग्रहण के साथ जुड़ी किसी पर्याप्त लागत को नहीं देता है और जेएनपीटी को भेजी जा रही है। बीओटी परिचालकों द्वारा वसूल किए गए प्रभार राजस्व हिस्सेदारी की वसूली के लिए देय नहीं होंगे क्योंकि यह आय नहीं है अपितु केवल जेएनपीटी के माध्यम से एसपीवी को प्रतिपूर्ति की जाती है। किन्तु, इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए बीओटी परिचालकों अर्थात् एनएसआईसीटीपीएल, जीटीआईपीएल द्वारा किए गए वास्तविक व्ययों को उनके तत्संबंधी नौजूदा प्रशुल्क की समीक्षा करते समय लेखा में लिया जा सकता है।
- (vi). जैसाकि घहले बताया गया है, टोल प्रभार कटेनरों, परियोजना कार्गो, द्रव्य कार्गो, सीमेंट तथा एलपीजी पर जेएनपीटी द्वारा वसूल किए जाने की परिकल्पना की गई है जोकि सड़क के लिए उपयोग किए जायेंगे। इस प्रकार, टोल प्रभार पाइपलाइनों के माध्यम से गुजरने वाले द्रव्य कार्गो, आईसीडी यातायात तथा पोतांतरण कार्गो पर वसूल किए जाने की परिकल्पना नहीं की गई है क्योंकि उक्त कार्गो संदर्भित सड़क के उपयोग के लिए नहीं होगा।
- (vii). वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान कार्गो मदों के यातायात तथा एमजेपीआरसीएल द्वारा सुविचारित कुल टोल संग्रह राशि को लेखा में लेते हुए, जेएनपीटी प्रस्तावित प्रभारों पर घहला है। प्रत्येक घटक पर नीचे दिए गए अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।
 - (क). जेएनपीटी ने वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान प्रहसित किए जाने वाले 4.77 मिलियन टीईथी तथा 5.35 मिलियन टीईयू यातायात का पूर्वानुमान लगाया है। उक्त यातायात जेएनपीटी में बीओटी परिचालकों अर्थात् एनएसआईसीटीपीएल, जीटीआईपीएल, एनएसआईजीटीपीएल तथा बीएसीटीपीएल के कटेनर यातायात का समावेशन देखा गया है। जेएनपीटी द्वारा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए यथा पूर्वानुमानित यातायात जेएनपीटी वार्षिक कार्गो यातायात लक्ष्य पर आधारित बताया गया है और इस विश्लेषण में विश्वास किया गया है।
 - (ख). वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान आईसीडी यातायात की औसत हिस्सेदारी 16.86 प्रतिशत बताई गई है। तथापि, 13.94 प्रतिशत की दर से अप्रैल से जून 2017 अवधि के लिए आईसीडी यातायात की हिस्सेदारी पर विचार करते हुए, कार्गो तथा अन्य प्रोत्साहनों के रेल तथा सड़क द्वारा निकासी द्वारा दरों को समान करने के मददेनजर जेएनपीटी ने वर्ष 2017-18 के लिए 15 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 के लिए 16 प्रतिशत की दर से आईसीडी यातायात की हिस्सेदारी पर विचार किया गया है। इस संबंध में पत्तन के निर्णय पर विश्वास किया गया है।

- (ग). हालांकि पोतांतरण कार्गों की हिस्सेदारी 2015–16 के लिए 1.14 प्रतिशत और 2016–17 के दौरान 0.99 प्रतिशत बताई गई है, जेनपीटी ने इस आधार पर कि पोतांतरण कार्गों में वृद्धि होगी, वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए 2 प्रतिशत की दर से एकसमान रूप से पोतांतरण कार्गों की हिस्सेदारी पर विचार किया है। विश्लेषण में इस रिपोर्ट पर विचार किया गया है।
- (घ). हालांकि वर्ष 2016–17 के दौरान ले जाए गए सड़क द्वारा द्रव्य कार्गों यातायात की मात्रा लगभग 34 लाख मीट. थी, परन्तु जेनपीटी ने इस आधार पर वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए 26 लाख मीट. की दर से एकसमान द्रव्य कार्गों यातायात पर विचार किया है कि सड़क द्वारा ले जाया गया द्रव्य कार्गों यातायात विभिन्न कारकों जैसे आयात मात्रा, रेल द्वारा आवागमन आदि पर निर्भर करता है, जैसे वर्ष दर वर्ष आधार पर भिन्न-भिन्न होगा। इस संबंध में पत्तन के निर्णय पर विश्वास किया गया है।
- (ङ). वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए 7.35 लाख मीट. तथा 7.70 लाख मीट. की दर से सीमेंट तथा अन्य कार्गों की मात्रा जेनपीटी वार्षिक कार्गों यातायात लक्ष्य पर आधारित बताई गई है और इसलिए विश्लेषण में इसपर विश्वास किया गया है।
- (च). $1 \text{ टीईयू} = 12 \text{ मीट.}$ के परिवर्तन कारक पर विचार करते हुए, जेनपीटी द्वारा द्रव्य, सीमेंट तथा अन्य कार्गों को टीईयू में परिवर्तित करने देखा गया है। द्रव्य कार्गों के परिमाप की इकाई टनभार के अनुसार है। इस प्रकार, टीईयू में कुल यातायात जिसपर टोल वसूल किया जाना है, जेनपीटी द्वारा 2017–18 में 4237017 टीईयू तथा 2018–19 में 4664553 टीईयू पर विचार किया गया है।
- (छ). एमजेपीआरसीएल द्वारा जेनपीटी को यथा संप्रेषित अनुमानित कुल टोल संग्रह राशि वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान क्रमशः रु. 109.12 करोड़ तथा रु. 114.58 करोड़ देखी गई है। इस संबंध में, यह विदेत है कि वर्ष 2016–17 के दौरान परिकल्पित रु. 103.93 करोड़ के टोल संग्रह के विपरीत, वर्ष 2016–17 के दौरान वास्तविक टोल संग्रह रु. 90.40 करोड़ बताया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2016–17 में रु. 13.53 करोड़ के टोल संग्रह में कमी वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान जेनपीटी द्वारा वसूल किए जाने वाले टोल से अच्छा रहने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए अनुमानित टोल संग्रह में टोल संग्रह की कमी का निर्णय करते हुए, जेनपीटी वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान वसूल किए जाने वाले सामान्य टोल प्रभार पर पहुंचा है। जेनपीटी द्वारा ऐसे निर्धारित सामान्य टोल प्रभार कंटेनरों के लिए रु. 267.56 प्रति टीईयू, परियोजना कार्गों तथा द्रव्य कार्गों के लिए रु. 22.30 प्रति मीट. और एलपीजी तथा सीमेंट के लए रु. 5/- प्रति मीट. है। इस संबंध में गणनाएं अनुबंध रूप में संलग्न किया गया है।
- विचार करते हुए कि सीमेंट तथा एलपीजी कीमत संबंदनशील घटक हैं, जेनपीटी ने रु. 22.30 के लगभग 75 प्रतिशत के लिए रियायत का प्रस्ताव किया है और इसलिए रु. 5/- प्रति मीट. की दर प्रस्तावित की गई है।
- (viii). यह विचार करते हुए कि यह प्रस्ताव भारत सरकार की कारोबार को आसान बनाने की नीति के मददेनजर तथा जेनपीटी को जाने वाली सड़कों को भीझराहित करने के लिए तैयार किया गया है, यह प्राधिकरण वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए अप्रैल 2017 के अपने संशोधित प्रस्ताव में पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित टोल प्रभारों की वसूली के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रवृत्त है।
- (ix). यह यदि किया जाए कि पत्तन द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, यह प्राधिकरण जेनपीटी को उसके द्वारा उसके अप्रैल 2016 प्रस्ताव में यथा प्रस्तावित टोल प्रभारों की अंतरिम आधार पर वसूली करने के लिए पहले ही प्राधिकृत किया गया है, परन्तु इस शर्त के अधीन कि यदि इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अंतिम दरों प्रस्तावित दरों से कम रहती हैं तो अंतिम दरों तथा तदर्थ दरों के बीच का अंतर जेनपीटी द्वारा संबद्ध उपयोक्ताओं को वापिस किया जाएगा। दिया गया है कि तदर्थ आधार पर जेनपीटी द्वारा वसूल की गई दर (कंटेनरों के लिए रु 240/- प्रति टीईयू, परियोजना कार्गों/द्रव्य कार्गों के लिए रु 20/- प्रति मीट. तथा सीमेंट एवं एलपीजी के लिए रु. 5/- प्रति मीट.) इस प्राधिकरण द्वारा (अनुमोदित की जाने वाली) अंतिम टोल दरों (कंटेनरों के लिए रु 267/- प्रति टीईयू, परियोजना कार्गों/द्रव्य कार्गों के लिए रु 22/- प्रति मीट. तथा सीमेंट एवं एलपीजी के लिए रु. 5/- प्रति मीट.) से कम है, इसलिए उपयोक्ताओं को अंतरिम अवधि के दौरान वसूल किए गए टोल प्रभारों के मामले में जेनपीटी द्वारा वापिसी का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके विपरीत, वर्ष 2016–17 के लिए वसूली में कमी को वर्ष 2017–18 के लिए वसूलीयोग्य दरों की गणना में लिया गया है।
- (x). प्रशुल्क नीति को कार्यान्वित करने के लिए जारी कार्य दिशानिर्देशों के साथ पठित प्रशुल्क नीति, 2015 में कार्यनिष्पादन मानकों का निर्धारण विनिर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, जेनपीटी से टोल प्रभारों की वसूली के संबंध में कार्यनिष्पादन मानकों का प्रस्ताव करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में, जेनपीटी ने बताया है कि चूंकि वसूली टोल गेटों पर टोल समाप्त किए जाने की वजह से है, इसलिए इससे जुड़े कार्यनिष्पादन मानक लागू नहीं किए जा सकते।
- (xi). जेनपीटी के लिए निर्धारित टोल प्रभार वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए अनुमानों पर आधारित है। इस बात की ज्यादा संभावना है कि वास्तविकताएं अनुमानों से भिन्न होंगे। इसलिए, जेनपीटी को अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने हेतु टोल प्रभारों में अधिक वसूली (यदि कोई हो) को समायोजित करने अथवा कमी वसूली (यदि कोई हो) को सही करने की अनुमति दी गई है।

14.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, जेनपीटी के मौजूदा दरमान में अध्याय 6 – विविध प्रभार के अधीन खंड 6.7 रूप में निम्नलिखित प्रावधान का समावेश अनुमोदित किया गया है:-

“6.7: टोल प्रभार/उपयोक्ता शुल्क:

पत्तन शिपिंग लाइनों/एजेंटों/टैक फार्म ऑपरेटरों (सड़कमार्ग द्वारा डिलीवरी)/परेषित आदि) से सभी गेट कॉम्प्लेक्सों (जेनपीटी, एनएसआईसीटीपीएल, जीटीआईपीएल, एनएसआईजीटीपीएल, बीपीसीएल एवं बीएमसीटीपीएल में) में अन्दर और बाहर जाने वाले कंटेनर (टीईयू) और अन्य सामान्य कार्गो पर पत्तन निम्नलिखित प्रभार वसूल करेगा।

क्र.सं.	विवरण	टोल प्रभार ₹० में
1.	कंटेनर (प्रति टीईयू)	267/- प्रति मी.ट.
2.	सङ्कमार्ग द्वारा प्रहसित परियोजना कार्गों तथा द्रव्य कार्गों	22/- प्रति मी.ट.
3.	सीमेंट/एलपीजी	5/- प्रति मी.ट.

14.2. चूंकि जेएनपीटी के गेटों पर टोल की वसूली पहले से 01 मई 2016 से प्रचलन में है, और कार्गों संबंधित प्रभार होने के नाते संशोधित वसूली दरों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित है, टोल प्रभार 01 अक्टूबर 2017 से प्रभावी होंगे और जेएनपीटी के सामान्य संशोधन मामले में यथा अनुमोदित दरों की वैधता अर्थात् 31 मार्च 2019 तक सह—समाप्त रहेंगे। प्रदत्त अनुमोदन उसके बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जबतक कि इस प्राधिकरण द्वारा विशेषतः विस्तारित नहीं किया जाता है।

14.3. अब अनुमोदित टोल प्रभारों की वसूली की जेएनपीटी के प्रशुल्क की अगली सामान्य समीक्षा के समय समीक्षा की जाएगी। पत्तन को यह सलाह दी जाती है कि इस संबंध में अलग खाता व्यवस्थित करे और जेएनपीटी के प्रशुल्क की अगली समीक्षा के समय संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षित ब्यारे भेजे।

टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 256 / 17]

अनुबंध

जेएनपीटी में टोल प्रभारों की गणना

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
क.	कंटेनरयुक्त कार्गो (टीईयू में) घटाना: वर्ष 2016–17 के लिए 16.63 प्रतिशत, वर्ष 2017–18 के लिए 15 प्रतिशत और वर्ष 2018–19 के लिए 16 प्रतिशत की दर से आईसीडी यातायात घटाना: 2 प्रतिशत की दर से पोतांतरण कार्गो सङ्कमार्ग द्वारा कुल कंटेनरयुक्त कार्गो यातायात (टीईयू में)	4750000 789925 95000 3865075	4770000 715500 95400 3959100	5346000 855360 106920 4383720
ख.	जुक थोक (सीमेंट) तथा अन्य (मी.ट. में)	700000	735000	770000
ग.	द्रव्य कार्गो (सङ्कमार्ग द्वारा परिवहन किया जा रहा है) (मी.ट. में)	2580000	2600000	2600000
घ.	ख + ग का जोड़ (मी.ट. में)	3280000	3335000	3370000
ड.	कुल शुक्त थोक, परियोजना कार्गो तथा द्रव्य टीईयू में (1 टीईयू = 12 मी.ट.)	273333	277917	280833
च.	कुल यातायात जिसपर टोल संग्रहीत किया जाएगा (टीईयू में) (क + ड)	4138408	4237017	4664553
छ.	एमजेपीआरसीएल द्वारा सुविचारित कुल टोल संग्रह राशि (राशि रु. में)	1039300000	1091200000	1145800000
ज.	वर्ष 2016–17 के दौरान संग्रहीत टोल (राशि रु. में) वर्ष 2016–17 के लिए टोल संग्रह में कमी, वर्ष 2017–18 में अंतरित (राशि रु. में) 2017–18 तथा 2018–19 के लिए अप्रेक्षित कुल टोल संग्रह (राशि रु. में)	903954677 135345323 0	0 135345323 1226545323	0 0 1145800000
झ.	टोल दर प्रस्तावित प्रति टीईयू		289.48	245.64
ञ.	औसत टोल दर प्रस्तावित (प्रति टीईयू)		267.56	
ट.	सङ्कमार्ग द्वारा प्रहसित परियोजना कार्गों तथा द्रव्य कार्गों के लिए टोल दर (ज/12) (प्रति मी.ट.)		22.30	
ठ.	सीमेंट/एलपीजी के लिए रियायती दर (प्रति मी.ट.)		5.00	

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th September, 2017

No. TAMP/28/2016-JNPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), seeking approval for fixation of Toll Charges on Containers and other Cargo passing through JNPT due to closure of Toll Gates on NH-4B, SH-54, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/28/2016- JNPT

Jawaharlal Nehru Port Trust

...

QUORUM

Applicant

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachhar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 15th day of September 2017)

This case relates to a proposal received from Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) for charging of toll on Containers and Other Cargo passing through Port due to closure of Toll Gates on NH-4B, SH-54.

2.1 The JNPT vide its letter no. JNP/Fin/TAMP/2016 dated 27 April 2016 and email dated 28 April 2016 had filed a proposal for levy of toll charges with effect from 01 May 2016 on Containers and Other cargo passing in and out of all gate complexes of JNPT due to closure of the Toll Gates on NH-4B and SH-54.

2.2. The main points made by JNPT in its proposal are summarised below:

- (i). In view of heavy traffic congestion on account of toll gates of Special Purpose Vehicle (SPV) i.e. Mumbai JNPT Port Road Company Limited (MJPRCL) at roads of NH-4B and SH-54, Government has decided to close toll gates with effect from 1 May 2016 and the toll will be charged on containers (per TEU) and other general cargo going in and out of all Gate complexes instead of charging toll on vehicles, as is being collected by SPV i.e. MJPRCL at their toll plazas.
- (ii). In this connection, a copy of the letter No. MJPRCL/NHAI/PIU/Panvel/Toll/ 2016/297 dated 23.04.2016 received from MJPRCL as well as minutes of meeting with Joint Secretary (Highways) held on 25 February 2016 are furnished.
- (iii). The JNPT has to compensate MJPRCL for their loss of revenue by levying appropriate charges on container and other general cargo.
- (iv). The calculation for levying the toll charges is as follows:

Sr.	Description	Traffic in TEU/MT
A.	Containerized cargo	4750000 TEUs
	Less : ICD traffic for the year 2015-16 : 15.84% and for the year 2016-17 : 16.63%	789925 TEUs
	Less : Transshipment cargo2%	95000 TEUs
	Total traffic by road	3865075 TEUs
B.	Dry Bulk (Cement) & others	700000 MT
C.	Liquid Cargo (Being transported by Road)	
	i). Edible Oil & Molasses	1700000 MT
	ii). Chemicals	700000 MT
	iii). HSD by tankers	1800000 MT
	Total liquid traffic by road	2580000 MT
D.	Total of B + C	3280000 MT
E.	Total Dry Bulk, others and liquid in TEUS will be 3280000 MT/12MT	273334 TEUs
F.	Total traffic on which toll to be collected (A+E)	4138409 TEUs
G.	The total toll collection considered for year 2016-17 by NHAI (In ₹)	
	Chirle & Karanjade (NH-4B)	₹77.38 crs.
	Dastan Phata (SH-54)	₹21.68 crs.
	Total	₹99.06 crs
H.	Toll proposed rate per TEU (G/F)	₹239.36/TEU Say ₹240/TEU
I.	Rate for project cargo and liquid handled by road	₹20/MT
J.	Concession rate of cement / L.P.G.	₹5/MT

- (v). Accordingly, the toll proposed by JNPT is ₹240/TEU, ₹20/MT for project cargo and liquid handled by road and ₹5 per MT for cement as it is a price sensitive cargo. However, ₹5 per ton is also proposed for LPG as the trucks are arriving and utilizing the road network for transportation of empty cylinders to the bottling plant and going back with loaded cylinders. However, the charges will not be levied on liquid cargo passing through pipelines, ICD traffic, transhipment cargo, etc.
- (vi). Such charges recovered from BOT operators shall not be liable for levy of revenue share as the same is not income but only reimbursement to the SPV through JNPT on account of abolition of toll at Gates to reduce congestion and traffic jams.
- (vii). The revised charge on account of widening of existing NH-4B (A1-E section from km3.600 to km 27,270, D-G Section from km 0.000 to km 4.462) SH-54 (from km 5,300 to km 14,850) and Amra Marg (From 0.000 to km 6200) to 6/8 lanes on boundaries to proposed Navi Mumbai International Airport in the State of Maharashtra on EPC Mode will be intimated separately on completion of the same and arriving at effective date from which to levy the revised charges.
- (viii). The Port intends to levy such charges from 1 May 2016 to avoid loss of income to SPV i.e. MJPRCL. A formal trade notice will be issued separately.

3.1. The JNPT intended to levy the toll charges with effect from 1 May 2016. In this regard, it is relevant here to mention that any proposal for notification of rate for use of a new facility or a new service is to be forwarded to the TAMP at least 60 days prior to the expected date of commissioning of the new cargo facility or a new service, as stipulated in Clause 5.7.2 of the Working Guidelines. However, in the instant case, the proposal was received from JNPT on 27 April 2016 for intending levy of toll charges by JNPT with effect from 01 May 2016. Further, there was no mention about the consultation by JNPT with the concerned users as required under clause 5.7.4 of the Working Guidelines. Also, the proposal submitted by JNPT was found to be incomplete.

3.2. Nevertheless, owing to the paucity of time to approve the levy of toll charges by JNPT with effect from 1 May 2016 following the usual consultation process and since the Government has directed to stop the tolling at existing toll plaza and instead collect toll/user fee by JNPT at its gate complexes with effect from 1 May 2016, and also recognizing the intention of JNPT for levy of the proposed charges with effect from 1 May 2016 is to avoid loss of income to the Special Purpose Vehicle (SPV), the JNPT was authorized to collect Toll at the proposed charges with effect from 1 May 2016 on Container, Project Cargo, Liquid Cargo (Edible oil and Molasses, Chemicals, HSD by tankers, concessional rate of cement and L.P.G.) which are transported by road and going in and out of all gate complexes of JNPT as an interim measure subject to the following conditions :

- (i). The levy of proposed rates will be on adhoc basis till the rates are finally notified by this Authority.
- (ii). The adhoc rates to be operated and the Performance Standards to be applied in the interim period must be in consultation with the concerned users and the BOT Terminals operating at JNPT.
- (iii). If the final rates fixed by this Authority are lower than the proposed rates, the difference between the final rates and adhoc rates shall be refunded by the JNPT to the concerned users.

3.3. This position was communicated to JNPT vide our letter dated 29 April 2016.

3.4. Simultaneously, the JNPT was also requested vide our above referred letter to furnish some information so as to have a complete proposal. It was also communicated to JNPT that, the complete proposal to be filed by JNPT will be taken on consultation with the relevant stakeholders and a joint hearing will also be held and thereafter an Order would be passed by this Authority taking into account the totality of the information collected during the consultation proceedings. In response to this, the JNPT vide its letter dated 24 May 2016 has furnished the information. The information sought by us and the response of JNPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information sought by us	Response of JNPT
(i).	Minutes of the meeting held with the relevant stakeholders with regard to the proposal.	<p>The Minutes of the meeting of Stakeholders communicated by Ministry of Road Transport & Highways vide Office Memorandum No. RW/NH-37011/45/2014-PPP dated 13.04.2016, is furnished.</p> <p>[The meeting was convened on 25 February 2016 to discuss the issues pertaining to financing of SPV and tolling with respect to the project of 6/8 laning highway project of Port connectivity to JNPT in the State of Maharashtra. The Ministry of Road Transport & Highways, National Highways Authority, CIDCO and JNPT were represented in the meeting. The paragraphs of the Minutes relevant to the proposal in reference are reproduced below:</p> <p>(i). Regarding tolling/user fee, it was pointed out that the main user of this road is JNPT bound traffic and considering the traffic congestion at toll gates and the resistance shown by local commuters for tolling, it was agreed that the toll/ user fee may be collected by JNPT at its gate complexes till repayment of toll debt liability, from port traffic using the road connectivity. The existing toll plazas will be discontinued.</p>

		<p>(ii). JS(H) informed that, Hon'ble Minister (RT&H) has directed to stop the tolling at existing toll plazas and instead collect toll/ user fee by JNPT at its gate complexes with effect from 1 May 2016 till repayment of total debt liability.</p> <p>As recorded in para 2(i) of the Minutes, funds to the tune of ₹2439.66 Crores are required to be raised for execution of stage-II of the project (6/8 laning of NH-4B and SH-54). The funds are being arranged by JNPT through ECB funding upto USD 400 Million for MJPRCL]</p>																		
(ii).	Draft Scale of Rates alongwith Performance Standards.	<p>The following is proposed to be added under Chapter 6, Miscellaneous charges at point no. 6.7 :</p> <p>"6.7: Toll charges/ User fees:</p> <p>Port will collect the following charges on container (TEU) and other general cargoes going in and out of all Gate complexes (in at JNPT, NSICT, GTI, NSIGT & BPCL from Shipping Lines/ Agents/ Tank Farm operators (delivered by road)/ Consignee etc).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Particulars</th> <th>Amount of Toll charges</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Container (per TEU)</td> <td>₹240/TEU</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Project Cargo</td> <td>₹20/MT</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Liquid Cargo</td> <td>₹20/MT</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Cement</td> <td>₹ 5/MT</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>LPG</td> <td>₹5/MT</td> </tr> </tbody> </table> <p>Since this is a levy on account of abolition of Toll, there are no separate performance standard connected with the same.</p>	Sr. No.	Particulars	Amount of Toll charges	1.	Container (per TEU)	₹240/TEU	2.	Project Cargo	₹20/MT	3.	Liquid Cargo	₹20/MT	4.	Cement	₹ 5/MT	5.	LPG	₹5/MT
Sr. No.	Particulars	Amount of Toll charges																		
1.	Container (per TEU)	₹240/TEU																		
2.	Project Cargo	₹20/MT																		
3.	Liquid Cargo	₹20/MT																		
4.	Cement	₹ 5/MT																		
5.	LPG	₹5/MT																		
(iii).	List of users/user associations/BOT operators to be consulted with contact details like mailing address, fax No. and E-mail ID.	<p>The list of Users organization, BOT operators to be consulted and the Copy of the Trade Notice issued by JNPT to the Stakeholders is furnished.</p>																		
(iv).	Copy of the approval of the Board of Trustees of the Port with regard to the proposal in reference.	<p>The subject proposal was placed before the Board in the 8th Board Meeting held on 17 May 2016 and duly approved by the Board of Trustees.</p> <p>(The port has furnished a copy of the Agenda item and stated that the Minutes of the Board meeting will be sent separately)</p> <p>[Subsequently, the JNPT vide its letter dated 28 June 2016 has forwarded the Minutes of the Meeting.]</p>																		

4.1. While acknowledging the proposal, the JNPT was requested vide our letter dated 3 June 2016 to clarify the reason for not including the conditions specified by this Authority at the time of approving the adhoc rates in Trade Notice.

4.2. After reminders, the JNPT vide its letter dated 5 July 2016 has, interalia, stated that even though while issuing trade notice, conditionalities were not incorporated, JNPT conducted a detailed meeting with Container Shipping Lines Association (India) and other Stake-holders for charging of toll on containers and other cargo passing through the Port due to closure of Toll Gates at NH-4B and SH-54, wherein, it was clearly indicated that the rate approved by TAMP will be finally applicable after the same is obtained from TAMP. It was also discussed that, the rate circulated vide Trade Notice is an adhoc rate which will be finalized on receipt of official order from TAMP. Further, copy of minutes of another meeting held with terminal operator and Tank Farm Operators on 29 April 2016 is furnished.

5. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy each of the JNPT proposal dated 27 April 2016, 28 April 2016, our letter dated 29 April 2016 and JNPT letter dated 24 May 2016 was forwarded to the concerned users/ user organisations for their comments. Some of the user Organisations and BOT operators at the JNPT viz. The All India Liquid Bulk Importers & Exporters Association (AILBIEA), Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL), Federation of Indian Export Organisation (FIEO), Nhava Sheva (India) Gateway Terminal Private Limited (NSIGTPL) and Nhava Sheva International Container Terminal Private Limited (NSICTPL) vide their letters dated 9 June 2016, 10 June 2016, 10 June 2016, 14 July 2016 and 13 July 2016 respectively have furnished their comments, which were forwarded to the JNPT as feedback information. The JNPT vide its letter dated 5 July 2016 and 21 October 2016 has responded to the comments of the users.

6. While responding to the comments of the user Organisations and BOT operators, the JNPT vide its letter dated 5 July 2016 has also made the following submissions:

- (i). Under the Port road connectivity project, National Highway Authority of India (NHAI) had formed a Special Purpose Vehicle consisting of NHAI, JNPT and CIDCO for improvement to the existing road connectivity to the Port. In the Phase-I, 4 laning of NH-4B, SH-54 and Amra Marg was taken up. The work of widening of NH-4B was completed in 2005 and widening of Amra Marg was completed in the year 2008. NHAI/ SPV had commenced charging the toll at Toll Gates on these roads and toll was being collected as per the policy of NHAI.
- (ii). The local commuters and heavy vehicle owners had opposed the toll collection and transport unions had also declared strike. The matter was discussed with the transport unions, NHAI & CIDCO and after discussions it was decided to charge 50% toll for the local heavy vehicles registered in Raigad and Navi Mumbai. The passenger vehicles were given some concessions. In spite of this, the local public agitated for long queues at the toll gates and congestion on the roads from time to time.
- (iii). JNPT currently has a capacity of 4.2 mn Twenty Equivalent Units (TEUs) and has been operating at capacity utilization of ~100%. The current traffic at JNPT is being evacuated predominantly through road (around 80%) and balance through rail connectivity. However, the road capacity is fully utilized as the current traffic on these roads are estimated at 77,000 pcu (passenger car units) vis-à-vis capacity of 60,000 pcu.
- (iv). Taking into consideration the increased traffic, NHAI has taken up the work of widening of 6/8 laning of NH-4B, SH-54. As per Ministry of Surface Transport the whole road infrastructure is primarily for JNPT traffic and, therefore, the Port will be raising loan of ₹2600 crores out of total project cost of ₹2855 crores in order to fund the project. For the said purpose JNPT will be acquiring 51% share in the said SPV.
- (v). In view of public unrest and policy taken up by Government of Maharashtra, it was decided to collect the toll from the traffic handled at JNPT, instead of collecting the same at toll gates, which was causing the traffic jams.
- (vi). The toll amount to be collected during the period of construction of 6/8 lane road is captured in revenue forecast for road project. Hence, it needs to be collected to maintain projected cash flow.
- (vii). The underlying principle behind the proposal is to reduce congestion on Highway due to port traffic, collect toll at Port Gates to facilitate the hassle free movement on road. As a result of above measure, there is a visibly less traffic congestion on highways and consequently less congestion at port roads. Queuing up of trucks also leads to law and order problem as well as frequent jamming at Port gates etc.

7. The joint hearing in this case was held on 15 July 2016. At the joint hearing, the JNPT made a Power Point presentation of the proposal. The JNPT and the concerned users/ organization bodies have made their submissions at the joint hearing.

8.1. As agreed at the joint hearing, the JNPT was requested vide our letter dated 20 July 2016 to furnish some information/ clarification. After reminders dated 8 September 2016 and 24 October 2016, the JNPT vide its letter dated 21 October 2016 has responded. The information sought by us and the response of the JNPT thereon are tabulated below:

Sl. No.	Information sought by us	Response of JNPT
(i).	During the joint hearing, the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) had highlighted the difficulty being faced by them in the collection of toll charges. In this connection, the BPCL had requested the JNPT to collect the levy directly from the concerned and had expressed its willingness to provide necessary facility at its terminal for toll collection. Thus, as decided at the joint hearing, the JNPT to look into the matter, and furnish a Report in this regard after consulting BPCL	There is no provision for collecting toll at the gates of BPCL LPG Bottling Plant as it is very difficult to regulate and monitor the collection either by NHAI or JNPT and the whole purpose of avoiding congestion on road due to collection of toll will be defeated.
(ii).	During the joint hearing, the terminal operators viz., Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL), Nhava Sheva India Gateway Terminal Private Limited (NSIGTPL) and Nhava Sheva International Container Terminal Pvt. Ltd. (NSICTPL) had made a request to allow them to retain 5% of the collection amount towards administrative and related costs and the JNPT had also agreed to work upon a solution. Accordingly, the JNPT to look into the matter and submit their proposal.	The point made by NSICTPL, NSIGTPL and GTIPL regarding allowing them to retain 5% of the collection amount towards administrative and related cost cannot be agreed to as no such arrangement was envisaged at the time of discussion or in the MOU.
(iii).	Further, the JNPT has sought approval for the levy of the toll charges for a period of three years. Since the estimates have been furnished by JNPT only for the year 2016-17, the JNPT to take into account the estimates for the period of three years and formulate a proposal accordingly and file.	As regards estimated Toll collection for 2017-18 and 2018-19, the same has been taken up with SPV for furnishing details.
(iv).	The JNPT to furnish the basis for estimating each of the following for the year 2016-17: (a). Total Containerized cargo at 4750000 TEUs. (b). Share of ICD traffic considered at 16.63%. (c). Share of Transhipment Cargo at 95000 TEUs.	The basis for estimating traffic for the year 2016-17 is based on our letter to Ministry bearing ref. no. JNP/CM(T)/Traffic Target/2016-17 dated 18 January 2016. As per the said letter, the commodity wise tentative annual traffic targets for the year 2016-17 for JNPT, as communicated by JNPT to MOS is seen to be as follows:

		Sr. no.	Commodity	Target	
	(d). Share of Dry Bulk (Cement) & others at 700000 MT.	1	Liquid (Chemicals+POL) (Tonnes)	6,500,000	
	(e). Share of Liquid Cargo (being transported by Road)	2.	Dry Bulk (Cement) & others (Tonnes)	700,000	
	(i). Edible Oil & Molasses at 1700000 MT.	3	Containers		
	(ii). Chemicals at 700000 MT.		JNPCT+SDB (Tonnes)	20,955,000	
	(iii). HSD by tankers at 1800000 MT.		JNPCT+SDB (TEUs)	1,650,000	
			NSICT (Tonnes)	10,160,000	
			NSICT (TEUs)	800,000	
			NSIGT (Tonnes)	5,080,000	
			NSIGT (TEUs)	400,000	
			GTIPL (Tonnes)	24,130,000	
			GTIPL (TEUs)	1,900,000	
			Total Containers (Tonnes)	60,325,000	
			Total Containers (TEUs)	4,750,000	
			Grand Total (Tonnes)	67,525,000	
					This may be considered as traffic of JNPT for the year 2016-17
					The share of ICD and transhipment is based on actual mode of traffic handled for the year 2015-16. The liquid traffic for the year 2016-17 is estimated based on the liquid cargo handled in the year 2015-16. Out of the total estimated liquid cargo of 65,00,000 MT to be handled in the year 2016-17, cargo wide break-up of liquid cargo is as follows:
					(i). Edible Oil & Molasses – 17,00,000 MT.
					(ii). Chemicals – 7,00,000 MT.
					(iii). POL & POL products – 41,00,000 MT.
				Total - 65,00,000 MT.	
					All edible oil and molasses and chemical cargo are moved by road using tankers. Out of the POL, 1,80,000 MT of HSD belonging to Reliance Ltd. Is also moved by road and rest of the liquid cargo is moved through pipeline and rail. Hence, the total estimated liquid cargo to be moved by road for the year 2016-17 is 25,80,000MT. (17,00,000+7,00,000+1,80,000)
(v)	The total toll collection estimated for year 2016-17 by National Highway Authority of India (NHAI) for Chirle & Karanjade (NH-4B) at ₹77.38 crs. and Dastan Phata (SH-54) ₹21.68 crs respectively, thereby aggregating to ₹99.06 Cr. and considered as base by JNPT in its workings, to be substantiated by documentary evidence/ workings.				Dry Bulk (cement) and other cargo is moved by road only. The toll collection for the year 2016-17 by NHAI for Chirle & Karanjade (NH-4B) at ₹77.38 crores and Dastan Phata (SH-54) ₹21.60 crores respectively.
(vi).	The port has not furnished the basis/ workings to arrive at the concession Toll rate of ₹5 Per MT for Cement/ LPG. The basis/ workings to arrive at concessional toll rates to be furnished.				Cement and LPG are price sensitive commodities and therefore concessional rate of ₹5/- has been arrived at considering 75% concession.
(vii).	The toll charges in respect of Bulk Cargo, Liquid Cargo, Cement and LPG have been proposed on per tonne basis. Since the toll appears to be a levy towards passage of vehicles, it may be appropriate to prescribe toll charges in respect of above cargo items on per vehicle basis instead of per tonne basis. JNPT to look into it.				The toll charges in respect of Bulk Cargo, Liquid Cargo, Cement and LPG, has been notified on per tonne basis as the same is related to cargo passing through the Port road (due to closure of Toll Gate on NH-4B and SH-54). It is very difficult to identify and collect from the transporters in whose vehicle the commodity will be transported. This is not only logical but also administratively easy to implement.

8.2. With regard to the request made by JNPT during the joint hearing to enable them levy the toll charges for a period of 3 years, the JNPT was requested to formulate and to file a proposal by taking into account the estimates for a period of 3 years. The JNPT was periodically reminded vide our letters dated 8 September 2016, 24 October 2016, 17 November 2016, 06 December 2016, 14 February 2017 and 19 April 2017.

9.1. In this backdrop, the JNPT has responded vide its letter dated 27 April 2017. The submissions made by JNPT are as follows:

- (i). Based on JNPT's request, the Mumbai JNPT Road Company Limited (MJPRCL) vide its letter dated 3 April, 2017 has furnished following tentative toll collection for next three years:

Year	Amount
2016-17	₹103.93 crores
2017-18	₹109.12 crores
2018-19	₹114.58 crores

- (ii). Further as per JNPT's projections the traffic figures for 2017-18 and 2018-19 are as per the details given below:

Sr. No.	Commodity	Financial Year	
		2017-18	2018-19
1	Liquid (Chemicals+POL) (Tonnes)	7,000,000	7,500,000
2	Dry Bulk (Cement) & others (Tonnes)	675,000	700,000
3	Break Bulk	60,000	70,000
4	Containers		
	JNPCT+SDB (Tonnes)	20,557,800	20,938,500
	JNPCT+SDB (TEUs)	1,620,000	1,650,000
	NSICT (Tonnes)	10,152,000	10,152,000
	NSICT (TEUs)	800,000	800,000
	GTIPL (Tonnes)	22,842,000	23,476,500
	GTIPL (TEUs)	1800,000	1,850,000
	NSIGT (Tonnes)	5,076,000	6,928,740
	NSIGT (TEUs)	400,000	546,000
	BMCTPL (Tonnes)	1,903,500	6,345,000
	BMCTPL (TEUs)	150,000	500,000
5	Total Containers (Tonnes)	60,531,300	67,840,740
6	Total Containers (TEUs)	4,770,000	5,346,000
	Grand Total (Tonnes)	68,266,300	76,110,740

- (iii). Further based on such projection, after adding the shortfall of ₹13.53 crores for the financial year 2016-17, the toll rates proposed for 2017-18 and 2018-19 are as follows -

Description	2017-18	2018-19
Toll rate proposed per TEU	₹ 267/TEU	₹ 267/ TEU
Toll rate for Project Cargo & Liquid Cargo handled by road	₹ 22/ MT	₹ 22/ MT
Concessional toll rate for Cement/ LPG	₹ 5/MT	₹ 5/MT

- (iv). Detailed calculations for arriving at the proposed rate, are as follows:

- (a). Statement showing Annual Traffic Projection for the year 2017-18 & 2018-19 and calculation for charges to be levied for recovering Toll income as projected by MJPRCL.

Sr. No.	Description	Traffic in TEUs/MT 2017-18	Traffic in TEUs/MT 2018-19	Total
A.	Containerized cargo	4770000 TEUS	5346000 TEUs	10116000
	Less: ICD traffic Considered for the year 2017-18: 15% Considered for the year 2018-19: 16%			
		715500 TEUS	855360 TEUs	1570860
	Less: Transshipment cargo 2%	95400 TEUS	106920 TEUs	202320
	Total Containerized cargo Traffic by road	3959100 TEUs	4383720 TEUs	8342820

B.	Dry Bulk (Cement) & Others	735000 MT	770000 MT	1505000
C.	Liquid Cargo (Being transported by Road)			
	Total liquid cargo Traffic by road	2600000 MT	2600000 MT	5200000
D.	Total of B + C	3335000 MT	3370000 MT	6705000
E.	Total Dry Bulk, Project Cargo & liquid in TEUs will be 3275000 MT/12MT	277917 TEUS	280833 TEUs	558750
F.	Total Traffic on which toll to be collected (A + E)	4237017 TEUS	4664553 TEUs	8901570
G.	The Total Toll collection amount considered for the year 2017-18 & 2018-19 by MJPRCL	₹ 1091200000		
	Add: Shortfall on Toll collection for 2016-17	₹ 135345323		
	Total Toll collection required for 2017-18 & 2018-19	₹ 1226545323	₹ 1145800000	2372345323
H.	Toll rate proposed per TEU	₹ 267/TEUs	₹ 267/TEUs	
I.	Toll Rate for Project Cargo & liquid cargo handled by road	₹ 22 /MT	₹ 22 /MT	
J.	Concessional rate for Cement/LPG	₹ 5 /MT	₹ 5 /MT	

(b). Statement showing shortfall in Toll collection for the year 2016-17.

Sr. No.	Description	Amount (in ₹)
A.	Toll Income as per estimate of MJPRCL	1039300000
	Less: collected by MJPRCL for the Month April 2016	83400000
	Less: Collected by JNPT during the Period from May 2016 to March 2017	820554677
	Shortfall in Toll Collection	135345323

9.2. A comparative position between the earlier proposal dated 27 April 2016 and the revised proposal dated 27 April 2017 is tabulated below:

Description	As per earlier proposal dated 27.4.16	As per Revised proposal dated 27.4.17	
		2017-18	2018-19
Toll rate proposed per TEU	₹ 240/TEU	₹ 267/TEU	₹ 267/ TEU
Toll rate for Project Cargo & Liquid Cargo handled by road	₹20/ MT	₹ 22/ MT	₹ 22/ MT
Concessional toll rate for Cement/ LPG	₹ 5/MT	₹ 5/MT	₹ 5/MT

10. Given that the JNPT has furnished the estimates for the years 2017-18 and 2018-19 and since there were changes in the toll charges now proposed by JNPT vis-à-vis toll charges proposed earlier, it was decided to take the revised proposal of JNPT on consultation with the relevant users/ user organisations and BOT operators. Accordingly, a copy of the JNPT revised proposal dated 27 April 2017 was forwarded to the concerned users/ user organisations/ BOT operators for their comments. The BOT operators viz. Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL), Nhava Sheva (India) Gateway Terminal Private Limited (NSIGTPL) and Nhava Sheva International Container Terminal Private Limited (NSICTPL) vide their letters dated 15 June 2017, 30 June 2017 and 30 June 2017 respectively have furnished their comments, which were forwarded to the JNPT as feedback information. The JNPT vide its letter dated 28 July 2016 has responded to the comments of the BOT operators.

11. The joint hearing on the revised proposal was held on 30 June 2017. At the joint hearing, the JNPT made a Power Point presentation of the proposal. The JNPT and the concerned users/ organization bodies have made their submissions at the joint hearing.

12. Further, during the joint hearing, additional information/ clarification were sought from JNPT. Accordingly, the JNPT has responded vide its letter dated 21 July 2017. The information/ clarification sought by us and response of JNPT thereon is tabulated below:

Sr. No.	Information/ Clarification Sought by us	Response of JNPT						
(i).	The JNPT to furnish the basis for ICD Traffic @ 15% & 16% considered for 2017-18 and 2018-19 respectively.	<p>As Regards ICD Traffic @ 15% and 16% considered for 2017-18 and 2018-19 respectively, we wish to state that ICD traffic for the last 3 years is as follows:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">2014-15</td><td style="text-align: center;">18.65%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015-16</td><td style="text-align: center;">17.27%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016-17</td><td style="text-align: center;">14.66%</td></tr> </table> <p>However during June 2017 there has been improvement and is 15.02% even though for the financial year 2017-18 i.e. April to June 2017 is 13.94% and with rail/road equalization and other incentives given it is projected that ICD traffic will be 15% for 2017-18 and 16% for 2018-19.</p>	2014-15	18.65%	2015-16	17.27%	2016-17	14.66%
2014-15	18.65%							
2015-16	17.27%							
2016-17	14.66%							
(ii).	The JNPT to furnish the basis for Transhipment Cargo @ 2% for both the years.	As regards Transhipment Cargo it was 1.14% for 2015-16 and 0.99% during 2016-17. It is expected that Transhipment Cargo will increase and therefore 2% has been considered for both the years.						
(iii).	The JNPT to furnish the basis for Quantum of liquid cargo traffic moved by Road.	As regards quantum of liquid cargo traffic moved by Road, it is taken constant at 26,00,000 on a safer side even though in 2016-17 it was around 34 lakhs M.T. It however depends on import volume, commodities and movement by rail which may vary on a year to year basis.						
2.	The JNPT to explain how the toll rate @ ₹22 per MT for project cargo and liquid cargo handled by road has been worked out.	As regards Toll Rate @ ₹22 per MT for project cargo and liquid cargo handled by road, it is to clarify that the rate to be arrived at is for different type of cargo and to have a common denominator, for project cargo and liquid cargo it was taken as 12 MT equal to 1 TEU. This is based on past trend for container traffic and accordingly projected traffic for liquid cargo and project cargo was converted into TEU and once rate per TEU was arrived at R ₹267 dividing the same by 12 M.T., the rate works out ₹22 per MT.						
3.	The JNPT in its proposal has stated that the levy of toll charges on containers and other cargo by JNPT is to compensate the Special Purpose Vehicle (SPV) viz Mumbai JNPT Port Road Company Limited (MJPRCL) for their loss of revenue. However, the Minutes of the stakeholders meeting held on 25 February 2016 under the Chairmanship of Joint Secretary (Highways), Ministry of Road, Transport & Highway (as forwarded by JNPT under cover of its letter no. JNP/FIN/FA/2016/2848 dated 24 May 2016) makes a mention about JNPT raising funds to the tune of ₹2439.66 Crores through ECB and the discontinuance of collection of toll/ user fees by JNPT once the total debt liability is repaid. There is no clarity in the purpose for which the toll is proposed to be levied. Further, while the requisite funds from ECB has been quantified the loss to the SPV due to closure of Toll gates has not been quantified.	It is the fact that JNPT has raised ECB loan of 400 Million Dollar for financing 6/8 laning of SH-54 and NH 4B. The present toll being recovered is on account of improvement made under Phase I and toll was being levied for maintenance of road. In order to avoid traffic congestion at toll gates, a decision was taken to discontinue toll collection at gates and levy on cargo passing through JN Port. There is no loss to SPV on account of closure of toll gate as the same is being recovered on cargo passing through JN Port and being remitted to MJPRCL. The expected toll collection projection have been furnished by MJPRCL and based on traffic projection toll rate has been worked out. Once 6/8 laning is completed, revised rates will have to be worked out for increase cost incurred on such expansion and debt servicing obligation and other costs associated with it.						

13. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i). The Special Purpose Vehicle (SPV) formed by the NHAI had completed the 4 laning of the roads which connect the JNPT in Phase-I of the port connectivity project in the years 2005/2008 and commenced charging of toll at Toll Gates on these roads and the toll was being collected as per the policy of the NHAI for improvement made under

Phase-I and for maintenance of these roads. In view of heavy traffic congestion at roads of NH-4B and SH-54 from time to time reportedly arising on account of long queues at the toll gates put up by the SPV i.e. Mumbai JNPT Port Road Company Limited (MJPRCL), the Government, in keeping up with its policy of Ease of doing business has decided to close the said toll gates with effect from 1 May 2016. Since the traffic bound for Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) use these roads, it was decided by the Government that the toll/ user fee shall be collected by the JNPT at its gate complexes, from the port goods traffic which use the road connectivity. Accordingly, the JNPT has come up with a proposal to enable it levy of toll charges on Containers, Project Cargo, Liquid Cargo, Cement and LPG, on account of closure of Toll Gates.

- (ii). The initial proposal filed by JNPT was in April 2016. This proposal was to enable the port to levy toll charges on various cargo items during the year 2016-17 only. However, during the joint hearing held on the case in reference on 15 July 2016, the JNPT made a request to approve the toll charges for a period of three years. The JNPT was, therefore, requested to formulate a proposal taking into account the estimates for a period of three years. After continuous reminders, the JNPT has furnished the revised proposal in April 2017 after collecting the requisite details from NHAI in April 2017. This revised proposal of JNPT alongwith the information/ clarification furnished by JNPT during the processing of the case is taken into account in the analysis.
- (iii). The JNPT, in its initial proposal, had stated that the levy of toll charges on containers and other cargo by JNPT is to compensate the SPV viz., MJPRCL for their loss of revenue due to closure of Toll Gates. However, the Minutes of the stakeholders meeting held on 25 February 2016 under the Chairmanship of Joint Secretary (Highways), Ministry of Road, Transport & Highway (as forwarded by JNPT under cover of its letter no. JNP/FIN/FA/2016/2848 dated 24 May 2016) made a mention about JNPT raising funds to the tune of 400 Million Dollars through ECB and the discontinuance of collection of toll/ user fees by JNPT once the total debt liability is repaid. In this regard, the JNPT has clarified that the present toll being recovered is on account of improvement and maintenance of road and that once the 6/8 laning of SH-54 and NH 4B is completed, it will rework the rates so as to capture the costs incurred on expansion, debt servicing obligation and other costs associated with it.
- (iv). Based on a specific request made by JNPT, the JNPT was authorized to collect Toll at the charges as proposed by it in its April 2016 proposal, with effect from 1 May 2016 on Container, Project Cargo, Liquid Cargo (Edible oil and Molasses, Chemicals, HSD by tankers, concessional rate of cement and L.P.G.) which are going in and out of all gate complexes of JNPT as an interim measure subject to certain conditions, as already brought out in the earlier part of the Order.
- (v). Since the toll charges are envisaged to be levied at the JNPT Gate complexes, as per JNPT, the BOT Operators at JNPT are required to collect the toll charges and pay the same to JNPT who in turn would pay it to the SPV. In this connection, the said BOT operators are of the view that since the BOT operators will have to deploy additional resources for billing, collection and other administrative work, the terminal should be allowed to retain 5%-10% of the collection amount towards administrative and related costs. The JNPT has expressed its inability to agree for retention of some amount of the collection amount on the ground that no such arrangement was envisaged at the time of discussion or in the MOU. According to JNPT, the toll is only a line item in the regular bills being raised, JNPT does not foresee any substantial cost associated with collection of toll and remitting it to JNPT. The charges recovered by BOT operators shall not be liable for levy of revenue share as the same is not income but only reimbursement to the SPV through JNPT. Nevertheless, the actual expenses incurred by BOT operators viz. NSICTPL, GTIPL and BPCL towards rendering these services can be taken into account while reviewing their respective existing tariff.
- (vi). As brought out earlier, the toll charges are envisaged to be levied by the JNPT on Containers, Project Cargo, Liquid Cargo, Cement and LPG, which will be utilizing the road. Thus, the toll charges are not envisaged to be levied on liquid cargo passing through pipelines, ICD traffic and transhipment cargo, as the said cargo will not be making use of the road under reference.
- (vii). Taking into account the Total Toll collection amount considered by MJPRCL and the traffic of the cargo items during the years 2017-18 and 2018-19, the JNPT has arrived at the proposed toll charges. Each of the components are discussed in the paragraphs hereinunder:
 - (a). The JNPT has projected a traffic of 4.77 million TEUs and 5.35 million TEUs to be handled during the year 2017-18 and 2018-19 respectively. The said traffic is seen to be inclusive of the container traffic of the BOT operators at JNPT viz., NSICTPL, GTIPL, NSIGTPL and BMCTPL. The traffic as projected by JNPT for the years 2017-18 and 2018-19 is reported to be based on the JNPT annual cargo traffic target and is relied upon in the analysis.
 - (b). The average share of ICD traffic during the years 2014-15 to 2016-17 is reported to be 16.86%. However, considering the share of ICD traffic for the period from April to June 2017 at 13.94%, the JNPT has considered share of ICD traffic at 15% for the year 2017-18 and 16% for the year 2018-19 keeping in view the equalisation of rates by rail and road evacuation of cargo and other incentives. The judgment of the port in this regard is relied upon.
 - (c). Though the share of Transhipment Cargo is reported to have been 1.14% for 2015-16 and 0.99% during 2016-17, the JNPT, on the ground that Transhipment Cargo will increase, has considered the share of transhipment cargo uniformly at 2% for the years 2017-18 and 2018-19. This position is considered in the analysis.
 - (d). Though the quantum of liquid cargo traffic moved by Road during the year 2016-17 was around 34 lakhs MT, the JNPT has considered uniform liquid cargo traffic at 26 lakhs MT for the years 2017-18 and 2018-19, on the ground that liquid cargo traffic moved by Road depends on various factors viz., import

volume, movement by rail etc., which shall vary on a year to year basis. The judgment of the port in this regard is relied upon.

- (e). The quantum of Cement and Other Cargo at 7.35 lakhs MT and 7.70 lakh MT for the years 2017-18 and 2018-19 is reported to be based on the JNPT annual cargo traffic target and hence is relied upon in the analysis.
- (f). By considering a conversion factor of 1 TEU = 12 MTs, the JNPT is seen to have converted the liquid, cement and other cargo into TEUs. The unit of measurement of liquid cargo is in terms of tonnage. Thus, the total traffic in TEUs on which toll is to be collected has been considered by JNPT at 4237017 TEUs in 2017-18 and 4664553 TEUs in 2018-19.
- (g). The tentative total Toll collection amount as communicated by MJPRCL to JNPT is seen to be ₹109.12 crores and ₹114.58 crores during the years 2017-18 and 2018-19 respectively. In this connection, it is understood that as against the toll collection of ₹103.93 crores envisaged during the year 2016-17, the actual toll collection during the year 2016-17 is reported to be ₹90.40 crores. Thus, the shortfall in the toll collection to the tune of ₹13.53 crores in the year 2016-17 is proposed to be made good from the toll to be levied by JNPT during the years 2017-18 and 2018-19. Thus, by building the shortfall of toll collection to the tentative Toll collection amount for the years 2017-18 and 2018-19, the JNPT has arrived at a common toll charge to be levied during the years 2017-18 and 2018-19. The common toll charge so arrived by JNPT is ₹267.56 per TEU for containers, ₹22.30 per MT for Project Cargo & liquid cargo and ₹5/- per MT for LPG and Cement. The workings in this regard is attached as **Annex**. Considering that Cement and LPG are price sensitive commodities, the JNPT has proposed for about 75% of ₹22.30 as concession and has, therefore, proposed a rate of ₹5/- per MT.
- (viii). Considering that the proposal has emanated in view of Government's policy of Ease of doing business and for decongesting the roads leading to the JNPT, this Authority is inclined to grant approval for the levy of toll charges as proposed by the Port in its revised proposal of April 2017, for the years 2017-18 and 2018-19.
- (ix). It may be recalled that based on the request made by the port, this Authority has already authorized JNPT to levy the toll charges as proposed by it in its April 2016 proposal on an interim basis, subject to the condition that if the final rates fixed by this Authority are lower than the proposed rates, the difference between the final rates and adhoc rates shall have to be refunded by the JNPT to the concerned users. Given that the rate levied by the JNPT on adhoc basis (₹240/- per TEU for containers, ₹20/- per MT for Project Cargo/ Liquid Cargo and ₹5/- per MT for Cement and LPG) is lower than the final toll rates (to be) approved by this Authority (₹267/- per TEU for containers, ₹22/- per MT for Project Cargo/ Liquid Cargo and ₹5/- per MT for Cement and LPG), the question of JNPT making any refund in respect of the toll charges levied during the interim period to the users does not arise. On the contrary, the shortfall in the collection for the year 2016-17 has been captured in the calculation for rates leviable for the year 2017-18.
- (x). The Tariff Policy, 2015, read with the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Policy stipulates prescription of Performance Standards. Accordingly, the JNPT was requested to propose Performance Standards with regard to the levy of Toll charges. In this regard, the JNPT has stated that since the levy is on account of abolition of Toll at Toll Gates, no performance standard connected with the same, can be made applicable.
- (xi). The toll charges fixed for JNPT is based on the estimates for the years 2017-18 and 2018-19. It is most likely that the actuals shall be different from estimates. Therefore, the JNPT is permitted to make good the shortfall collection (if any) or adjust the excess collection (if any), in the toll charges to be fixed for the next cycle.

14.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the insertion of the following provision as Section 6.7 under Chapter 6 – Miscellaneous Charges, in the existing Scale of Rates of JNPT is approved:

“6.7: Toll charges/ User fees:

Port will collect the following charges on container (TEU) and other general cargoes going in and out of all Gate complexes (at JNPT, NSICTPL, GTIPL, NSIGTPL, BPCL & BMCTPL) from Shipping Lines/ Agents/ Tank Farm operators (delivered by road)/ Consignee etc)

Sr. No.	Particulars	Toll charges in ₹
1.	Container (per TEU)	267/- per TEU
2.	Project Cargo & Liquid Cargo handled by road	22/- per MT
3.	Cement / LPG	5/- per MT

14.2. Since the levy of toll at the Gates of JNPT is already in vogue since 01 May 2016, and the revised levy being a cargo related charge for which no definite lead period is required for implementation of the rates, the toll charges shall come into effect from 01 October 2017 and shall remain co-terminus with the validity of the rates as approved in the

general revision case of JNPT i.e. 31 March 2019. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

14.3. The levy of the toll charges approved now shall be reviewed at the time of next general review of tariff of JNPT. The port is advised to maintain a separate account in this regard and furnish the audited details for scrutiny at the time of the next review of tariff of JNPT.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./256/17]

Annex

CALCULATION OF TOLL CHARGES AT JNPT

Sr. No.	Description	2016-17	2017-18	2018-19
A.	Containerized cargo (in TEUs) Less: ICD traffic @ 16.63% for the year 2016-17, 15% for the year 2017-18 and 16% for the year 2018-19 Less: Transshipment cargo @ 2% Total Containerized cargo Traffic by road (in TEUs)	4750000 789925 95000 3865075	4770000 715500 95400 3959100	5346000 855360 106920 4383720
B.	Dry Bulk (Cement) & Others (in MTs)	700000	735000	770000
C.	Liquid Cargo (Being transported by Road) (in MT)	2580000	2600000	2600000
D.	Total of B + C (in MT)	3280000	3335000	3370000
E.	Total Dry Bulk, Project Cargo & liquid in TEUs (1 TEU = 12 MT)	273333	277917	280833
F.	Total Traffic on which toll to be collected (in TEUs) (A + E)	4138408	4237017	4664553
G.	Total Toll collection amount considered by MJPRCL (Amount in Rs.)	1039300000	1091200000	1145800000
H.	Toll collected during the year 2016-17 (Amount in Rs.) Shortfall in Toll collection for 2016-17, transferred to the year 2017-18 (Amount in Rs.) Total Toll collection required for 2017-18 & 2018-19 (Amount in Rs.)	903954677 135345323 0	0 135345323 1226545323	0 0 1145800000
I.	Toll rate proposed per TEU		289.48	245.64
J.	Average Toll rate proposed (per TEU)			267.56
K.	Toll Rate for Project Cargo & liquid cargo handled by road (J/12) (per MT)			22.30
L.	Concessional rate for Cement/LPG (per MT)			5.00